

ग्राम कचहरी सचिवों ने निकाला आक्रोश मार्च

सरकार के सौतेलेपन रवैए के विरुद्ध ग्राम कचहरी सचिवों ने निकाला आक्रोश मार्च। सम्मानजनक मानदेय की मांग पूरी होनेतक जारी रहेगा आंदोलन।

ग्राम कचहरी सचिवों को दस वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भी बिहार सरकार के द्वारा महज तीन हजार रुपये प्रतिमाह की मानदेय में वृद्धि किये जाने के फैसले से आक्रोशित प्रखंड क्षेत्र के ग्राम कचहरी सचिवों ने सरकार के निर्णय की निंदा करते हुए प्रखंड



मुख्यालय परिसर से आक्रोश मार्च निकाल कर पूरे बाजार का भ्रमण किया। इस दौरान बिहार कैबिनेट के फैसले की प्रतियां फाड़कर रोष प्रदर्शन किया गया तथा बिहार सरकार सुनो गुहार मानदेय कर दो तीस हजार के नारे

बुलंद की। आक्रोश मार्च के समापन पर ग्राम कचहरी सचिवों का एक शिष्टमंडल बीडीओ को अपने मांगों का ज्ञापन सौंपा। आक्रोश मार्च का नेतृत्व ग्राम कचहरी सचिव संघ के प्रखंड अध्यक्ष सुनील पासवान ,पंच

सरपंच संघ के अरविंद कुमार तथा न्यायमित्र सुनिल कुमार कुशवाहा ने संयुक्त रुप से किया। आक्रोश मार्च प्रखंड के सभी ग्राम कचहरियों से जनप्रतिनिधि एवं कर्मी शामिल थे। इन लोगों के द्वारा कहा गया कि विगत दस

वर्षों से लगातार बिहार सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों एवं समाचारपत्रों के माध्यम से मानदेय में दोगुना या उससे अधिक वृद्धि की खबरें मंत्री एवं मुख्यमंत्री के स्तर से आती रही पर मंगलवार को महज तीन हजार रुपये की वृद्धि करना महाधोखा है।संच इसकी घोर निंदा करते हुए ग्राम कचहरी सचिव पद की गरिमा एवं कार्यभार तथा मंहगाई वृद्धि के मद्देनजर तीस हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग करता है। मांगें नही पूरी होने तक सड़क पर ही नहीं विधानसभा चुनाव में भी पूरा ग्राम कचहरी परिवार सरकार के विरुद्ध मतदान करेंगे। कहा गया कि अबतक ग्राम कचहरी एवं पुस्तकालय संचालन के कार्यों के अलावे सरकार के

सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे चुनाव,जनगणना,आयुष्मान अभियान, राजस्व महा अभियान एवं अन्य सभी महत्वाकांक्षी कार्य जी जान से करते आ रहे हैं। पर अभी जबतक समुचित मानदेय वृद्धि नहीं होगी हम सभी अन्य प्रतिनियुक्तियों पर कार्य का बहिष्कार जारी रखेंगे और जनहित को होनेवाले असुविधा के लिए बिहार सरकार जवाबदेह होगी। जिलाध्यक्ष कुमार गौरव ने बताया कि मांगे पूरी होने तक राज्य संघ द्वारा चरणबद्ध आंदोलन जारी रखी जाएगी। इनके आक्रोश मार्च को देखकर समाज के हर व्यक्ति का यही कहना था कि यह सरकार का घोर अन्याय है और सरकार को यथाशीघ्र इनके मानदेय वृद्धि पर पुनर्विचार करना चाहिए।

बाजरे के खेत में पेड़ से लटकी लाश मिली जांच में जुटी पुलिस



देश का दर्पण,दैनिक अखबार पत्रकार. राकेश कोठेनिया हलेना नदबई (भरतपुर) लालचाह रोड स्थित एक बाजरे के खेत में शनिवार को ग्रामीणों ने पेड़ से लटका एक व्यक्ति का शव देखा तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों ने तुरंत नदबई पुलिस को सूचना दी। शव करीब 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना पर सीओ अमर सिंह राठौड़, थानाधिकारी बृजेंद्र सिंह पुलिस जाणा के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम की भी बुलाया गया। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 40 वर्ष प्रतीत हो रही है और उसने पेंट व शर्ट पहन रखी थी। शव की हालत से अंदाजा लगाया जा रहा है कि व्यक्ति की मौत कई दिन पहले हुई है। हालांकि अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों में सूचना भिजवाई है और ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मामला आत्महत्या का है या हत्या कर शव लटकाया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा।

पुलिस थाना मालपुरागेट में अवैध मादक पदार्थ तस्कर प्रदीप सांसी को गिरफ्तार कर कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 11.90 ग्राम स्मैक बरामद



देश का दर्पण न्यूज पुलिस उपायुक्त (अपराध) अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जयपुर शहर में चलाये जा रहे ऑपरेशन "क्लीन स्वीप" के तहत जयपुर शहर में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु श्री रिछपाल सिंह, अति॰ पुलिस उपायुक्त संगठित अपराध के निकट सुपरविजन एवं नेतृत्व में सी.एस.टी. आयुक्तालय जयपुर की टीम के द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध पुलिस थाना मालपुरागेट जयपुर पूर्व में संयुक्त कार्यवाही करते हुए मादक पदार्थ तस्कर प्रदीप सांसी पुत्र श्री विजय सांसी को गिरफ्तार कर 11.90 ग्राम स्मैक बरामद की गई।

शिप्रापथ थाना क्षेत्र से चोरी की 01 मोटर साईकिले व 01 स्कूटी बरामद



देश का दर्पण न्यूज पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम श्री हनुमान प्रसाद ने बताया कि दुपहिया वाहन चोरी की रोकथाम हेतु वाहन चोरो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसकी पालना में श्री आलोक सिंघल अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम श्री सुरेन्द्र सिंह राणावत सहायक पुलिस आयुक्त झोटवाडा के सुपरवीजन में थानाधिकारी थाना करधनी श्री सवाई सिंह के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं में पूर्व से चालानशुदा अभियुक्तों एवं मुखबीर तंत्र विकसित कर वाहन चोरी की घटना में लिप्त सदस्यों पर निगरानी की गई। थाना करधनी पर गठित टीम के सदस्यों ने महत्वपूर्ण आपराधिक आसूचना प्राप्त करते हुये दिनांक 5.9.2025 को रात्रि के समय करधनी स्कीम के पास से शांति वाहन चोर 1. बादल सोनी पुत्र श्री बिहारी लाल जाति सोनी उम्र 32 साल मकान नं 210 गोपी नगर नो डुकान कालवाड रोड थाना करवनी जयपुर 2. विशाल वर्मा पुत्र श्री राकेश वर्मा जाति बलाई उम्र 28 साल निवासी मकान नं 21 मोती विहार गोकुलपुरा थाना करधनी जयपुर 3. संजय तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार जाति ब्राह्मण उम्र 42 साल निवासी मकान नं 57 गार्डन रेजीडेंसी गौविन्दपुरा थाना करधनी जयपुर को धारा 170 बी एन एस एस में गिरफ्तार किया जाकर उनके कब्जे से दिनांक 27.8.2025 को शिप्रापथ जयपुर क्षेत्र से चोरी की गई स्कूटी नं आर जे 14 जे के 7812 एवं दिनांक 1.9.2025 को शिप्रापथ जयपुर क्षेत्र से चोरी की गई होण्डा होरनेट मोटर साईकिल नं आर जे 08 एस यू 2992 चुराई गई बरामद की गई। तीनों अभियुक्तगण पूर्व से सम्पत्ती सम्बन्धी अपराधों में चालानशुदा है। अभियुक्तों से पूछताछ जारी है।

उज्जैन: ब्रिज से शिप्रा नदी में गिरी तेज रफ्तार कार, सर्चिंग जारी

उज्जैन/ब्यूरो। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शनिवार की रात एक तेज रफ्तार कार ब्रिज पर बेरिंकिंग नहीं होने के चलते अनियंत्रित होकर शिप्रा नदी में जा गिरी। बताया जा रहा है कि कार में तीन लोग सवार थे। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन नदी में तेज बहाव होने से कार सवार की तलाश में दिक्कतें आ रही हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वाहन अनियंत्रित होकर पिलर से टकराया और सिंधा नदी में गिर गया। कार में तीन लोगों के होने की संभावना जताई जा रही है। मौके पर प्रशासनिक अमला मौजूद है। पुलिस ने वहां क्रैन भी बुलाई है। एनडीआरएफ नदी में बोट चलाकर रेस्क्यू में जुटी है। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि जूना सोमवारिया की ओर से कार बड़नगर की ओर जा रही थी। कार ब्रिज के लेफ्ट साइड की ओर गिरी है। नदी पुल से करीब 12 फीट नीचे है। हादसे की वजह अभी सामने नहीं आ सकी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और होमागई के जवान बोट से सर्च कर रहे हैं।

सी.एस.टी. (क्राइम ब्रांच) आयुक्तालय जयपुर द्वारा थाना जवाहर नगर एवं थाना मोतीडूंगरी जयपुर में वाहन चोरी की वारदात का खुलासा

देश का दर्पण न्यूज पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जयपुर शहर में वाहन चोरी, नकबजनी एवं अन्य चोरी की बढ़ती वारदातों को मध्यनजर रखते हुए में क्राइम ब्रांच की सीएसटी को आसूचना संकलित कर वाहन चोरों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु श्री रिछपाल सिंह, अति. पुलिस उपायुक्त, संगठित अपराध के निकट सुपरविजन एवं नेतृत्व में उ.र.ळ. आयुक्तालय जयपुर की टीम द्वारा वाहन चोरों के विरुद्ध आसूचना संकलन पुलिस थाना जवाहर नगर एवं मोती डूंगरी जयपुर (पूर्व) में कार्यवाही की गई।



BSNL विभाग की केवल चोरी करने वाला मुख्य मुल्जिम गिरफ्तार

देश का दर्पण न्यूज श्री करण शर्मा पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर ने बताया की दिनांक 27.08.2025 को परिव्रादी श्री भोजराज सैनी उपमण्डल अभियंता केकेबल बीएसएनएल एमआई रोड जयपुर ने थाना जालपुरा जयपुर उत्तर पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट BSNL की केबल चोरी की पेश की आदि पर मु.न. 154/2025 धारा 303(2) BNS (2023) व 3 PDPP Act में दर्ज कर माल मुल्जिमान की तलाश प्रारम्भ की गई।



वारदात का खुलासा हेतु श्री बजरंग सिंह अति. पुलिस उपायुक्त द्वितीय के निर्देशन में श्री अनुप सिंह सहायक पुलिस आयुक्त वृत्त कोतवाली जयपुर के पर्यवेक्षण में श्री हवाईसिंह पुनि. थानाधिकारी पुलिस थाना जालपुरा जयपुर उत्तर, के नेतृत्व में श्री गिरधारी लाल हैड कानि न. 2106 पुलिस थाना बालुपुरा जयपुर उत्तर, श्री शिवराज कानि न.10064 श्री सतवीर कानि न. 11966 श्री महावीर कानि नं. 6961 श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह कानि न. 7795 की एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा घटना स्थल के आस पास लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरो की फूटेज चेक किये गये एवं फूटेज के आधार पर संदिग्ध शक्स की तलाश कर मुल्जिमान अब्दुल अलीम, फिटु शेख, मोहम्मद गवास को बाद अनुसंधान गिरफ्तार कर मुल्जिमानों के कब्जे से प्रकरण हाजा का माल मशरुका बीएसएनएल की 02 प्राईमरी केकेबल व घटना में काम मे लिये गये एक 04 फीट पाईप पोने इंच लोहे का, एक लोहे का सम्बल 2.5 फीट करीब, एक सवा दो फिट लोहे का पाईप पोने इंच वाला, एक छोटी हथोड़ी, एक टॉर्च छोटी, एक फावडा, एक लोहे की मिट्टी खोदने की बोगी लोहे के पाईप से जुडी हुई कुल लम्बाई करीब तीन फिट, दो प्लास्टिक के खाली कट्टो व एक ओटो रिक्शा को जब्त किया गया। वारदात का मुख्य मुल्जिम रहीफूल शेख प्रकरण दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था जो अपने किराये के मकान पर नहीं जा रहा था स्वर्ण जयन्ति नाला मे छुपकर फरारी काट रहा था मुल्जिम के पास रुपये नहीं होने के कारण कोई बड़ी वारदात को अन्जाम देकर पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में था जिसको टीम द्वारा अथक प्रयास एवं मुखबिर खास की सूचना पर दक्षिण दो जाकर मुल्जिम रहीफूल शेख को गिरफ्तार किया गया उक्त प्रकरण में तीन मुल्जिम पूर्व में गिरफ्तार किये जा चुके है। मुल्जिमान नशे के आदी है जिनहोने नशे के रुपये नहीं होने पर उक्त चोरी की। वारदात के संबंध में मुल्जिम से गहन अनुसंधान जारी है।

बुंदेलखण्ड की भूमि वीरों की भूमि : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल/ब्यूरो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की भूमि वीरों की भूमि है। बुंदेली भाषा का निरंतर प्रचार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड की उत्पत्ति से लेकर ऐतिहासिक काल और वर्तमान काल तक शौर्य, साहित्य-सृजन, लोक गीत- संगीत के विकास और कलाओं के उन्नयन की विशेषताओं का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार की शाम भोपाल के रवीन्द्र भवन में बुंदेली समामग में विभिन्न प्रतिभाओं के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।

के शुरू हो जाने से पुनपुन पिंडदान स्थल आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। साथ ही पुनपुन शहर के लोगों को व्यापार और रोजमर्रा की गतिविधियों में भी बड़ा सहारा मिलेगा। यह बिहार का पहला हल्के वाहनों के लिए बना केबल सस्पेंशन ब्रिज है।

ये खासियत इसे बनाती हैं खास पुल की कुल लंबाई 320 मीटर है सस्पेंशन डेक 120 मीटर लंबा है पुल को संभालने वाली स्टील की 18 मजबूत केबलें हैं पाईलॉन की ऊंचाई 100 फीट रखी गई है संपर्क पथ 135 मीटर और डक्ट की



लंबाई 200 मीटर है 46 करोड़ से शुरू होकर 83 करोड़ में तैयार इस पुल का निर्माण कार्य 31 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। शुरूआती लागत 46 करोड़ 77 लाख रुपये तय हुई थी, लेकिन समय के साथ बढ़कर लगभग 83 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

भोपाल/ब्यूरो। मध्य प्रदेश के दूरस्थ गांवों में नल से जल पहुंचने से जीवन आसान हो गया है। राजगढ़ जिले की ग्राम पंचायत चौंदपुरा का छोटा-सा दूरस्थ गांव समलाबेह इसका आदर्श उदाहरण है। नल से जल की सुविधा मिलने से यह गांव नई पहचान बन गया है। मोहनपुरा ग्रामीण समूह जल प्रयास योजना के अंतर्गत यहां की 130 की आबादी और 26 परिवारों तक घर-घर पाइपलाइन से स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। पानी की कमी से जूझता यह गांव अब सुविधा, स्वास्थ्य और खुशहाली की ओर अग्रसर है।

जनसम्पर्क अधिकारी बबीता मिश्रा ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ वर्ष पहले तक इस गांव का जीवन बेहद कठिन था। पानी के लिए महिलाओं और बच्चों को रोज सुबह-शाम कई किलोमीटर दूर कुओं से पानी लाना

पड़ता था। बरसात के मौसम में जब गंदा पानी इन स्रोतों में मिल जाता था तो ग्रामीणों को दूषित जल पीना पड़ता था। गर्मियों में गांव में पानी का संकट बढ़ जाता था। सीमित जलस्रोतों पर निर्भरता के कारण आए दिन झगड़ों की स्थिति भी बनती थी। इन परिस्थितियों से बच्चों की पढ़ाई और ग्रामीणों की आजीविका प्रभावित हो रही थी।

उन्होंने बताया कि समूह नलजल योजना ने इस गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। अब गांव के हर घर में पाइपलाइन से जलापूर्ति हो रही है। 26 घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है।

महिलाएँ बताती हैं कि पहले उनका आधा दिन पानी ढोने में ही निकल जाता था। अब यही समय परिवार और अन्य कार्यों को दे पा रही हैं। बच्चों को भी पानी लाने के काम से मुक्ति मिली है और उनकी पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी है।

स्वास्थ्य के स्तर पर भी बड़ा बदलाव आया है।

पहले बारिश के दिनों में डायरिया, उल्टी-दस्त और अन्य जलजनित बीमारियाँ आम थीं। अब ग्रामीण साफ पेयजल का उपयोग कर रहे हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और इलाज पर होने वाला खर्च भी कम हो गया है।

मोहनपुरा समूह जल योजना केवल समलाबेह तक सीमित नहीं है। यह योजना राजगढ़ जिले के कई गांवों को कवर कर रही है, जिनमें हजारों परिवारों तक नल के जरिए स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। योजना का उद्देश्य पूरे क्षेत्र को स्थायी जलस्रोत उपलब्ध कराना है।

ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल सुविधा नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक

जीवन की नींव है।

अब पानी के लिए नहीं करना पड़ता है संघर्ष: नौरंग बाई

वर्षों तक पानी ढोने को मजबूर रहें, गांव की 70 वर्षीय नौरंग बाई बताती हैं कि जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष पानी ही रहा। रोजाना सिर पर घड़ा रखकर पानी ढोना उनकी दिनचर्या थी। बरसों तक पानी की एक-एक बाल्टी के लिए कतार में खड़े रहना पड़ा। अब घर में नल लगने से यह संघर्ष बीते जमाने की बात हो गयी है। वे कहती हैं कि अब नई पीढ़ी को पानी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ग्रामीण भी मानते हैं कि नल से जल की व्यवस्था ने उनके जीवन स्तर को ही नहीं, पूरे गांव की सोच और संस्कृति को भी बदल दिया है। अब पानी केवल आवश्यकता नहीं रहा, बल्कि सम्मान, स्वास्थ्य और खुशहाली का प्रतीक बन गया है।

गजमार पहाड़ी बनेगा इको पार्क: वित्त मंत्री चौधरी ने किए 8 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन

रायगढ़/रायपुर/ब्यूरो। रायगढ़ जिले की ऐतिहासिक और आस्था से जुड़ी गजमार पहाड़ी अब आधुनिक स्वरूप में इको पार्क और इको-टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित होगी। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज शनिवार को 8 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों का भूमि पूजन कर परियोजना की शुरूआत की। इस अवसर पर उन्होंने पूजा-अर्चना कर पवनपुत्र हनुमान जी से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। परियोजना के तहत गजमार पहाड़ी पर योग प्लेटफॉर्म, वॉच टॉवर, पाँच पगोड़ा, बच्चों के लिए खेल परिसर, कैटीन और इको पार्क जैसी सुविधाएँ विकसित की जाएगी।



चौधरी ने कहा कि, यह केवल धार्मिक स्थल का जीर्णोद्धार नहीं, बल्कि रायगढ़ के सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यटन विकास की

दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि गजमार पहाड़ी रायगढ़ की शान है और इसका विकास शहर को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगा।

आस्था के साथ हुआ इंजीनियरिंग का मेल

सी एम नीतीश ने पुनपुन सस्पेंशन ब्रिज के जरिए पर्यटन, व्यापार और आस्था को जोड़ा

पटना/ब्यूरो। बिहार की धरती पर अब ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले जैसा नजारा दिखने वाला है। पटना से सटे पुनपुन में 320 मीटर लंबा आधुनिक केबल सस्पेंशन ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अनोखे ब्रिज का उद्घाटन किया और इसे आम लोगों के लिए खोल दिया। इस पुल

के शुरू हो जाने से पुनपुन पिंडदान स्थल आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। साथ ही पुनपुन शहर के लोगों को व्यापार और रोजमर्रा की गतिविधियों में भी बड़ा सहारा मिलेगा। यह बिहार का पहला हल्के वाहनों के लिए बना केबल सस्पेंशन ब्रिज है।

ये खासियत इसे बनाती हैं खास पुल की कुल लंबाई 320 मीटर है सस्पेंशन डेक 120 मीटर लंबा है पुल को संभालने वाली स्टील की 18 मजबूत केबलें हैं पाईलॉन की ऊंचाई 100 फीट रखी गई है संपर्क पथ 135 मीटर और डक्ट की

युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए सांसद नवीन जिन्दल की नई पहल नवीन जिन्दल स्पोर्ट्स एकेडमी

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नवीन जिन्दल स्पोर्ट्स एके-डमी का किया उद्घाटन

हरियाणा के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए नवीन जिन्दल स्पोर्ट्स एके-डमी का हुआ उद्घाटन हुआ

कैथल (कृष्ण प्रजापति):



केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को ओपी जिन्दल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, राई,

सोनीपत में नवीन जिन्दल स्पोर्ट्स एकेडमी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिन्दल

को इस पहल के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह स्पोर्ट्स एके-डमी न केवल ओ.पी. जिन्दल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्रों के

अतिवृष्टि तथा बाढ़ प्रभावितों को पहुंचाएं त्वरित राहत, पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर करें फसल खराबे की गिरदावरी - जवाहर सिंह बेदम



आपदा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को दी जाने वाली सहायता की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से आकाशीय बिजली गिरने तथा पानी में डूबने से हुई मौतों पर दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को तत्काल मुआवजा स्वीकृत करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिला

लिए लाभकारी होगी, बल्कि पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों को भी विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगी। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिन्दल ने कहा कि शिक्षा के साथ खेलों को भी समान महत्व देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और इसी कारण प्रदेश को दुनिया में मेडल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि इस एकेडमी में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही उन्होंने हरियाणा के भीम अवाड़ी और अर्जुन अवाड़ी खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे यहां अभ्यास कर

युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन दें। कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए अर्जुन अवाड़ी, भीम अवाड़ी और द्रोणाचार्य अवाड़ी खिलाड़ी भी शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। नवीन जिन्दल स्पोर्ट्स एकेडमी के उद्घाटन समारोह में हरियाणा के भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा, सुभाष बराला, सोनीपत विधायक निखिल मदान, पुंडरी विधायक सतपाल जांबा और गुहला के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर भी मौजूद रहे।

वरिष्ठजन व दिव्यांगजनों को सक्षम बनाएगा समर्थ धौलपुर अभियान,

जिला कलक्टर के प्रयासों से शुरू हुआ नवाचार, पहला शिविर 8 सितम्बर को सरमथुरा में

देश का दर्पण न्यूज,धौलपुर (धर्मेन्द्र बिधौलिया) 5 सितंबर। जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी के द्वारा जिले के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं को उनके घर के नजदीक ही उपलब्ध करवाने हेतु नवाचार के रूप में समर्थ धौलपुर अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले भर में 13 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में वरिष्ठजन और दिव्यांग जन को कृत्रिम अंग और उपकरण के लिए चिन्हित कर उपाय का वितरण किया जाएगा। शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत पहला शिविर सोमवार 8 सितंबर को पंचायत समिति सरमथुरा में तथा 9 सितंबर सोमवार को अटल सेवा केन्द्र आंगई के शिविर आयोजित होगा। शिविर में वरिष्ठ नागरिक आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेंशन पीपीओ या 1,80 लाख से कम का वार्षिक आय प्रमाण पत्र साथ लाकर सहायक यंत्र जैसे कान की मशीन, स्टीक, कमर की वैल्ट, घुटने की वैल्ट, साईकल कोलर, वॉकर, ट्राइपोड, वॉकिंग स्टिक आदि हेतु चिन्हीकरण किया करवा सकेगे। साथ ही दिव्यांगजन आवश्यक दस्तावेज यथा दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड , पैशन पीपीओ , फोटो लेकर दिव्यांग जन हेतु मोटराइज्ड ट्राई-साईकिल, व्हीलचेयर, कैलियर, वैश्याखी, वॉकर, ट्राईगोड, श्रवण यंत्र आदि हेतु चिन्हीकरण करवा सकेगे।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से अतिवृष्टि प्रभावित पंजाब में भेजी गई सहायता एवं राहत सामग्री

जयपुर, 06 सितंबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की जनकल्याणकारी सरकार संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एकात्म मानववाद के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए न सिर्फ प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए दिन-रात जुटे हुए है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य राज्यों का सहयोग करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। उल्लेखनीय है कि गत दिनों राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के दौरान श्री शर्मा ने सीमावर्ती क्षेत्र के जिला कलेक्टरसं को सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों तथा लोगों की मदद से पड़ोसी राज्य पंजाब में भारी बारिश से आयी आपदा में मदद भिजवाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से दानदाताओं एवं अन्य ट्रस्टों के माध्यम से 4 हजार राशन किट, 2 हजार 500 तिरपाल, 2 हजार पानी की बोतलें, 1 हजार मेडिकल किट, पशुओं के लिए 1 हजार चारा बैग, 40 ट्रेली चारा, सेना के समन्वय से 4 नावें तथा सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र से 15 लाख रुपए एवं आर्मी कैप से 11 लाख रुपए की सहायता राशि भिजवाई गई हैं। इसके अतिरिक्त गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर गुरुवार को राहत सामग्री भिजवाई गई जिसमें 200 राशन किट, 1700 तिरपाल एवं 1 हजार पानी की बोतल सहित अन्य सामग्री भिजवाई गयीं। मुख्यमंत्री के आह्वान एवं प्रेरणा से श्री गंगानगर जिले के पदमपुर उपखण्ड क्षेत्र से 2 लाख 26 हजार 800 रुपए की खाद्य सामग्री, 1 लाख 5 हजार रुपए की पानी की बोतलें, 186 बैग खलचूरी, 1 लाख 50 हजार रुपए का चारा तथा 1 लाख 46 हजार रुपए की नगद सहायता भेजी गई। उपखण्ड क्षेत्र श्री विजयनगर से विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा 150 किंवटल गेहू, पानी की 2 हजार 400 बोतल, ब्रिस्कट के 1000 पैकेट तथा 20 हजार रुपए की मेडिकल किट एवं दवाइयां भेजी गईं।

धौलपुर-शहर की सड़कें हुयीं क्षतिग्रस्त,बारिश के चलते हुये बड़े-बड़े गड्ढे, लोग हो रहे दुर्धटनाग्रस्त



देश का दर्पण न्यूज, धौलपुर (धर्मेन्द्र बिधौलिया) 5 सितंबर। शहर का गौरव पथ जिसे कभी शान और पहचान माना जाता था। अब गड्ढे से भरी सड़क में तब्दील हो चुका है। सड़क के दोनों ओर बीच सड़क में हुए बड़े-बड़े गड्ढे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन बाइक सवार और पैदल चलने वाले गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बरसात के दिनों में हालात और भी बिगड़ जाते हैं। पानी भरने से गड्ढों का पता ही नहीं चलता और लोग गिरकर चोटिल हो जाते हैं। कई बार छोटे हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग खामोश है। गौरव पथ पर स्थित निहाल टॉवर, सिटी जुबली हॉल और पुरानी टाऊन हाल जैसी रियासत कालीन इमारतें भी अब बदहाल स्थिति में नजर आने लगी हैं। पर्यटक यहां आते हैं लेकिन टूटी सड़कें और गड्ढों से भरा गौरव पथ शहर की छवि को लेकर खराब संदेश दे रहा है। यह मार्ग जनाना अस्पताल एवं शिशु रोग अस्पताल को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग भी है। जिससे मरीजों और एंबुलेंस का भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के डिवाइडर पर लगाए गए पौधे भी देख रेख के अभाव में झाड़ियां बन चुके हैं। उनकी शाखाएं दो से तीन फीट तक जालियों से बाहर सड़क पर फैल गई हैं, जो हादसे को आशंका को और बढ़ा रही हैं। शहरवासी अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब जिम्मेदार विभाग गौरव पथ की मरम्मत करेगा और शहर की इस धरोहर को फिर से गौरव दिलाएगा।

इवोक : दूसरे दिन जयगढ़ किले की ऐतिहासिक संध्या बनी आकर्षण का केंद्र

जयपुर
जयपुर में जारी इवोक 2025 का दूसरा दिन ऊर्जा, नवाचार और अनुभवों से भरा रहा। दिनभर विभिन्न पवेलियनों में आगंतुकों की भीड़ जुटी रही। देश के विभिन्न स्थानों जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, मुंबई, हैदराबाद आदि से आये एंटरप्रेन्योर्स ने डेकोर से लेकर फैशन, टेक्नोलॉजी, वेंडिंग प्लानिंग से लेकर हॉस्पिटैलिटी में चल रहे अत्याधुनिक ट्रेंड्स की 70 से अधिक स्टाल्स और पवेलियन के माध्यम से इवेंट इंडस्ट्री में सुजनशीलता और भविष्य की संभावनाओं की झलक प्रस्तुत की। बड़ी संख्या में आए मेहमानों ने इन पवेलियनों में दिलचस्पी दिखाई और आयोजकों तथा एंटरप्रेन्योर्स के साथ बातचीत कर सहयोग और साझेदारी के अवसर तलाशे इस अवसर पर बात करते हुए एईई के प्रिंसिडेंट समीर बाबेल ने कहा, "राजस्थान सदियों से कथ्य भारतीय शादियों का पर्याय रहा है। यहाँ की परंपरा, मेहमानवाजी और शाही अंदाज हर आयोजन को खास बना देता है।

उपखण्ड सुमेरपुर क्षेत्र जवाई बांध में लगातार आवक जारी है गेट के मुहाने तक पानी का लेवल पहुंच चुका है जवाई बांध में लगातार आवक जारी है गेट के मुहाने तक पानी का लेवल पहुंच चुका,लेकिन शनिवार 2:35 बजे जवाई बांध के गेट 2, 4, 10 गेट तीन गेट खोले दो, दो, फिट गेट एक गेट 1 फिट गेट खोला पानी का सैलाब मौके गेट खोलने देखने आए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत जवाई बांध के प्रभारी अधिकारी गणपत देवासी न्यूज रिपोर्ट डीके देवासी जानकारी लेते हुए हालांकि पानी की आवक को देखते हुए जवाई नहर खंड सुमेरपुर के एक्सईएन राज भंवरायत ने अलर्ट जारी किया अलर्ट में बताया कि बांध के पानी से टच नदी के आसपास रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट कैचमेंट एरिया में पानी की आवक एवं आगामी दिनों में मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट को ध्यान में देखते हुए बांध के गेट तीन गेट खोले एक्सईएन ने डाउन स्ट्रीम में जवाई नदी के बहाव क्षेत्र और उसके आस पास पानी के संभावित बहाव को देखते हुए सावधानी बरतने को निर्देशित किया

चन्द्रप्रभा रिसोर्ट होटल के पास खेत मे हरा चारा खा फोटोग्राफी करने के चक्कर मे खुला छोडा गाय और भैंस अंदर चली गई होटल रूम के आगे जमीन मे लाइट तार करंट छोड़ा हुआ 2 भैंस की मौत

उपखण्ड बाली कोठार चन्द्रप्रभा रिसोर्ट मे बिजली करंट लगने से मौत दो भैंस की मौत गांव मे चूसना दी 2 भैंस मालिक ने जोरसिंह/खोमसिंह चौहान कोठार पहले बोल दिया था रिसोर्ट ट्रिस्ट लोग फोटोग्राफी करने पहाड़ियों पर जाते इस छोटी गली गेट से जाते जोरसिंह ने पहले बोला इस तरह खुला नही छोड़े कभी भी पशु अंदर जानवर जाएगा चन्द्रप्रभा रिसोर्ट होटल के पास खेत मे फोटोग्राफी करने ये हादसा हुआ भैंस गाय अंदर जाने से हादसा हुआ गेट खुले से अंदर गए दो भैंसों को करंट लगने मौके पर ही मौत हो गई यह लापरवाही चन्द्र प्रभारिसोर्ट वालों की फोटोग्राफी से हादसे के लपेट मे आई दो भैंस मौके पर मौत हुई दिन को रिसोर्ट मे बिजली तारों को करंट के लिए खुला छोड़ा मौके पर दो भैंसों की मौत हो गई

विधायक लालाराम बैरवा ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शाहपुरा बनेडा में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की फसलों के नुकसान का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक

सुरज वर्मा शाहपुरा शहर में विधायक लालाराम बैरवा ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शाहपुरा बनेडा में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की फसलों के नुकसान का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने तीनों उपखंडों के उपखंड अधिकारियों और अन्य विभागों के अधिकारियों को शत-प्रतिशत फसल खराबे की गिरदावरी करने के निर्देश दिए, ताकि सभी प्रभावित किसानों को इसका लाभ मिल सके। बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों, सड़कों, विद्यालयों, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों की स्थिति पर चर्चा की गई।

क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। नदियों, तालाबों और बांधों के भरने पर आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने के लिए अलर्ट जारी किया गया। सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। तालाबों और बांधों के अधिकारियों को निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

हमारा इलाका, हमारा समाधान कैप में पहुँचे सुंदरबन विकास मंत्री, जनता की समस्याओं पर दिया आशवासन

रमेश राय गंगासागर: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर पूरे राज्य में चल रहे ह्रहमारा इलाका, हमारा समाधानह्र कार्यक्रम के तहत गंगासागर के मुरिगंगा 1 ग्राम पंचायत के अंतर्गत कचुबेरिया के 12 और 13 नंबर बूथ में शनिवार सुबह विशेष कैप का आयोजन हुआ। इस कैप में सुंदरबन विकास मंत्री एवं सागर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंकिमचंद्र हाजरा मौजूद रहे। उनके साथ सागर ब्लॉक के बीडीओ कनैया कुमार राव, सागर थाने के प्रभारी अप्पण नायक तथा पंचायत के कई अधिकारी भी उपस्थित थे। कैप में स्थानीय लोगों ने लंबे समय से उपेक्षित 115 मीटर सड़क (ग्रामाणिक पाड़ा, गोविंद मंदिर के पास) की मरम्मत की मांग उठाई। मंत्री ने स्थल निरीक्षण कर जल्द ही सड़क मरम्मत का काम शुरू करने का आशवासन दिया। इसके अलावा स्कूल भवन सहित कई समस्याएँ भी जनता ने उनके सामने रखीं, जिनके शीघ्र समाधान का भरोसा मंत्री ने दिया।

देश का दर्पण न्यूज,धौलपुर (धर्मेन्द्र बिधौलिया)6 सितंबर। राज्य मंत्री गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग व जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने शनिवार को धौलपुर जिले में अतिवृष्टि से उपजे हालातों और प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत कार्यों की गहन समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रभावितों की राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बैठक में प्रभारी मंत्री बेदम ने जिले में अब तक हुई मानसूनी वर्षा के आंकड़ों, अतिवृष्टि के कारण हुए विभिन्न प्रकार के नुकसान, और



(गोबली, श्वानबली, काक बली, देव बली और पिंपीलिका बली) करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें और उन्हें संतुष्ट करें। फिर श्राद्धकर्ता स्वयं भोजन ग्रहण करें। आचार्य शास्त्री ने कहा कि यदि कोई निर्धन है और व्यवस्थाएं नहीं कर सकता तो कम से कम पितरों के नाम से गाय को चारा खिलाना भी पर्याप्त

कोठार मे ख्यारी नदी गणपति विसर्जन किया तूफानी ख्यारी नदी चल रही इस दौरान काफी लोगोंो ग्रामीण देखने आए

उपखण्ड बाली क्षेत्र कोठार गांव रबारी समाज ने गणपति की स्थापना आज ख्यारी नदी में गणपति विसर्जन किया इस दौरान युवाओं ने सतर्कता दिखते हुए कोई लापरवाही नहीं करें पानी के अंदर कोई नही जाए कुछ लोगों ने नदी के ऊपर से गणपति बाबा मोरिया का विसर्जन किया कोठार गलीको लेकर आकरिया चौक आए वहा पर सम्पान



हुआ न्यूज रिपोर्ट डीके देवासी जानकारी

तेज बारिश से सड़के बनी नदियाँ और जलमग्न भीलवाड़ा: प्रशासन की खुली पोल

भीलवाड़ा शहर और जिले में दो दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। शुक्रवार शाम से शुरू हुई बारिश शनिवार सुबह तक जारी रही, जिससे शहर की सड़क तालाब में तब्दील हो गई। भारी जलभराव और बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर जसमीन सिंह संधू ने शनिवार, 6 सितंबर को जिले के समस्त सरकारी व निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है।भीलवाड़ा में शुक्रवार शाम से लगातार बारिश जारी रहने के कारण भीलवाड़ा शहर की मुख्य और गली-मोहल्लों की सड़कें पानी से लबालब हैं। शास्त्री नगर,सांगानेर रोड, संजय कॉलोनी आजाद नगर, पन्नाधाय सर्किल, मानसरोवर झील चौराहा, रोडवेज बस स्टैंड, सीताराम जी की बावड़ी जूनावास बड़ा मंदिर और रामधाम रोड समेत दर्जनों इलाकों में लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। अंडरब्रिज डूब गए, पांडु का नाला उफान पर है और सड़कों पर नदियां बहती नजर आईं। सिर्फ आसमान से बरसता पानी ही भीलवाड़ा की इस दुर्दशा का कारण नहीं है।



झोलाछाप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया लड़की की अचानक बिगडी मौत

देश का दर्पण.दैनिक अखबार पत्रकार. राकेश कोठेनिया हलेना भरतपुर.उच्चेन क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही ने एक मासूम जिंदगी छीन ली। मुररका निवासी 19 वर्षीय छात्रा सविता ने शनिवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सविता पिछले 25 दिनों से मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष कर रही थी। जानकारी के अनुसार, सविता अपने ननिहाल डलीराम निवासी जुगला पट्टी में रहकर पढ़ाई कर रही थी। करीब एक माह पहले उसे बुखार हुआ तो परिजन उपचार के लिए स्थानीय झोलाछाप डॉक्टर अशोक के पास ले गए। परिजनों का आरोप है कि मरीज के मना करने के बावजूद डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। गंभीर स्थिति में सविता को जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां लगातार इलाज चल रहा था। आज सुबह करीब आठ बजे इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सविता के नाना डलीराम ने झोलाछाप डॉक्टर अशोक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था। ग्रामीणों का कहना है कि कस्बे और आसपास के इलाकों में आज भी झोलाछाप डॉक्टर बेखौफ होकर आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।



प्रभारी सचिव ने किया फसल खराब और गिरदावरी कार्यों का निरीक्षण

बारां, राजस्थान
बारं, 6 सितम्बर। राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में जिला प्रभारी सचिव टीकमचंद बोहरा ने शनिवार को अन्ता तहसील क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर फसल खराबा एवं गिरदावरी कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से रूबरू होकर खेतों में खड़ी फसलों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने सबसे पहले पटवार मंडल पलायथा के पलायथा गाँव पहुंचकर वहां की फसलों का अवलोकन



प्रदेश की 15 प्रमुख मंडियों से भी ज्यादा सुमेरपुर की डीएलसी दरें -केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सीएम को कराया अवगत



जयपुर, 06 सितंबर। पाली जिले की सुमेरपुर कृषि उपज मंडी एकमात्र ऐसी मंडी है जिसके भूखंडों की डीएलसी की दरें राज्य की प्रमुख 15 मंडियों से कहीं ज्यादा है। हैरानीजनक बात ये है कि मंडी के गेट से बाहरी परिधि में डीएलसी की दरें मंडी से आधी भी नहीं है। इस बड़े अंतर के कारण मंडी के व्यापारी दुकानों की क्रय-विक्रय की रजिस्ट्री कराने की बजाय एग्रीमेंट करके ही व्यापार कर रहे हैं। इससे राज्य सरकार को राजस्व को कोई राजस्व नहीं प्राप्त हो रहा है। कृषि मंडी की डीएलसी दरें घटाने की मांग को लेकर स्थानीय विधायक व पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को अवगत कराया है। इस पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जल्द ही इसमें संशोधन कर सुमेरपुर कृषि मंडी की डीएलसी दर कम करने का आश्वासन दिया।

16 प्रमुख मंडियों में से डीएलसी दरें सर्वाधिक मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बताया कि सुमेरपुर की महाराजा उम्मेद सिंह कृषि उपज मंडी समिति की डीएलसी दरें 4776 रुपए प्रति वर्ग फीट है। वहीं, मुख्य मंडी बालोतरा की डीएलसी दर 621 रुपए प्रति वर्ग फीट, बाड़मेर मंडी की 1750 रुपए, भगत की कोठी की 3564 रुपए, बिलाड़ा की दर 3765, जैसलमेर मंडी की दर 1990, जैतारण की 2376, जालौर की 2459, जोधपुर फल-सब्जी व अनाज मंडी की दर 3618, पाली मंडी की 3464, फलोदी मंडी की 2247 रुपए, पीपाड़ शहर मंडी की दर 3564, रानी स्टेशन मंडी की दर 2710 रुपए, सांचोर मंडी की दर 2491 रुपए, मुख्य मंडी सोजत रोड की दर 825 रुपए वर्ग फीट है। उन्होंने बताया कि सुमेरपुर मंडी परिसर के बाहर जवाई बांध रोड जो कि व्यवसायिक मार्केट है, उसकी डीएलसी दरें 2393 रुपए प्रति वर्ग फीट मुख्य मंडी प्रांगण के बाहर आर्य समाज से भुवनेश्वरी मंदिर तक है। इस प्रकार मंडी परिसर के बाहर 20 फीट दूरी पर ही मंडी परिसर से आधी डीएलसी दरें हैं। इस कारण व्यापारी दुकानों के क्रय-विक्रय की रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तथा एग्रीमेंट करके ही व्यापार कर रहे हैं। रजिस्ट्री नहीं होने से राज्य सरकार को पिछले 40 साल से राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है।

हमारा इलाका, हमारा समाधान कैप में पहुँचे सुंदरबन विकास मंत्री, जनता की समस्याओं पर दिया आश्वासन



रमेश राय
गंगासागर: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर पूरे राज्य में चल रहे हमारा इलाका, हमारा समाधान कार्यक्रम के तहत गंगासागर के मुरिगंगा 1 ग्राम पंचायत के अंतर्गत कचुबेरिया के 12 और 13 नंबर बूथ में शनिवार सुबह विशेष कैप का आयोजन हुआ। इस कैप में सुंदरबन विकास मंत्री एवं सागर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बकिमचंद्र हाजरा मौजूद रहे। उनके साथ सागर ब्लॉक के बीडीओ कनैया कुमार राव, सागर थाने के प्रभारी अर्पण नायक तथा पंचायत के कई अधिकारी भी उपस्थित थे। कैप में स्थानीय लोगों ने लंबे समय से उपेक्षित 115 मीटर सड़क (ग्रामाणिक पाड़ा, गोविंद मंदिर के पास) की मरम्मत की मांग उठाई। मंत्री ने स्थल निरीक्षण कर जल्द ही सड़क मरम्मत का काम शुरू करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा स्कूल भवन सहित कई समस्याएँ भी जनता ने उनके सामने रखीं, जिनके शीघ्र समाधान का भरोसा मंत्री ने दिया। मंत्री बकिमचंद्र हाजरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर यह कार्यक्रम राज्यव्यापी जनहितकारी अभियान बना है। पहाड़ से लेकर सागर, जंगलमहल से लेकर छिटमहल तक हर जगह हमारा पड़ोस, हमारा समाधान कैप आयोजित हो रहा है। पहले जनता को अपनी समस्याओं के लिए जनप्रतिनिधियों के पास दौड़ना पड़ता था, अब जनप्रतिनिधि खुद लोगों की दहलीज पर पहुँचकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इस अभियान से अब तक 10 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। सागर ब्लॉक बीडीओ ने बताया कि ब्लॉक में कुल 70 कैप आयोजित किए गए हैं, जिनमें से शनिवार को 48 कैप विभिन्न बूथों में चल रहे हैं। जनता अपनी समस्याएँ रख रही है और अधिकारियों द्वारा उन्हें लिखित रूप से दर्ज कर शीघ्र समाधान की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। छोटे मुद्दों का समाधान 7 दिनों में और बड़े मुद्दों पर 3 महीने के भीतर कार्य शुरू करने की योजना है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भगवान परशुरामजी सत्य व ज्ञान के प्रतीक हैं। भगवान परशुरामजी के आदर्शों को अपनते हुए श्री परशुराम ज्ञान पीठ में अध्ययन करने वाले बच्चों को ज्ञान, विज्ञान के साथ सनातन संस्कार की भी सीख दे। जिससे यहाँ से पढकर निकलने वाला हर बच्चा दुनिया में समाज व राष्ट्र का नाम रोशन करे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को विप्र फाउंडेशन की ओर से जयपुर के मानसरोवर में नवनिर्मित श्रीपरशुराम ज्ञानपीठ (सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च) के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। भगवान के जनकारों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री परशुराम ज्ञानपीठ के लिये विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक सुशील ओझा समेत अन्य



पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह बहुत ही अच्छे कार्य की शुरुआत हुई है। भगवान परशुरामजी की कृपा से पीठ की शुरुआत हुई है। समाज के हर गरीब व वंचित वर्ग को अच्छा ज्ञान मिले इसके लिए समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे केंद्र गाँवों तक खोले। तभी वंचित वर्ग के युवा आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण समाज के युवाओं के शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन के लिए श्रीपरशुराम ज्ञानपीठ (सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च) का निर्माण बड़ा ही

काइरोप्रेक्टिक थैरेपी कार्ड्रो प्रैक्टिकह एक ऐसा समायोजन जिसमें प्रशिक्षित विशेषज्ञ, जिन्हें काइरोप्रेक्टर्स कहते हैं

काइरोप्रेक्टिक थैरेपी कार्ड्रो प्रैक्टिकह एक ऐसा समायोजन जिसमें प्रशिक्षित विशेषज्ञ, जिन्हें काइरोप्रेक्टर्स कहते हैं जो अपने हाथों या किसी छोटे उपकरण के उपयोग से रीढ़ की हड्डी के जोड़ पर नियंत्रित बल लगाते हैं इस प्रक्रिया को ह्रस्पाइनल मैनिपुलेशनह भी कहते हैं। इसका मकसद रीढ़ की हड्डी की गति , शरीर की हड्डी के जोड़ों और शरीर की गति करने की क्षमता में सुधार करना है। गाँवों में पुराने समय में इन हकीमों को "हाड हकीम" या ह्हाड-पहलवानह भी कहते थे जो हड्डियों की मोच निकालने का काम किया करते थे उसी को आधुनिक समय में ह्हाकायरो प्रैक्टिसह कहते हैं। यह हड्डियों को स्वस्थ रखने वाली प्रणाली है जो शरीर के जोड़ों को प्राकृतिक उपचार पर जोर देती है, खासकर रीढ़ की हड्डी और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम (मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों) व्यवस्थित रखने में मदद करती है। हकीम या यूनानी चिकित्सक इसमें काइरोप्रेक्शनर का कार्य करते हैं। इस थैरेपी से रीढ़ की हड्डी और शरीर के अन्य हिस्सों में



समायोजन (मैनुअल थैरेपी) करते हैं, जिससे जोड़ों को सही जगह बैठाने, दर्द कम करने ,जोड़ों की गतिशीलता में सुधार किया जा सके और शरीर की प्राकृतिक कार्यप्रणाली को बढ़ावा दिया जा सके। काइरोप्रेक्टिक उपचार में आमतौर पर निम्न को शामिल हैं 1.मैनुअल थैरेपी रीढ़ की हड्डी और जोड़ों में हेरफेर करना, जिसे स्पाइनल मैनिपुलेशन कहा जाता है। 2.एक्सरसाइज रोगी को घर पर ही विशिष्ट व्यायाम के सुझाव दिये जाते हैं। 3.पोषण संबंधी परामर्श इसमें पोषण और सप्लीमेंट्स के बारे में सलाह दी जाती है।

किया। उन्होंने खेलों में जाकर सोयाबीन एवं अन्य खरीफ फसलों की स्थिति देखी। किसानों ने बताया कि इस बार बारिश अनियमित होने से फसलें प्रभावित हुई हैं, जिससे उत्पादन में भारी कमी की संभावना है। इस पर प्रभारी सचिव ने आश्चर्य किया कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव राहत दी जाएगी। इसके बाद प्रभारी सचिव बोहरा पटवार मंडल अमलसरा के गोपालपुरा ग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने गिरदावरी कार्य की प्रगति देखी। उन्होंने संबंधित पटवारियों एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश

दिए कि गिरदावरी कार्य पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से किया जाए ताकि वास्तविक हकदार किसानों को ही राहत और मुआवजा मिल सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खेत स्तर पर जाकर नुकसान का सही आकलन करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि वे गिरदावरी कार्य में राजस्व कर्मियों को सही जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि नुकसान का सटीक मूल्यांकन किया जा सके।



जयपुर, 6 सितम्बर 2025। शिक्षक दिवस के अवसर पर समाज में शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को सरहाने और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा का महत्व समझाना के लिए लायंस क्लब जयपुर डायमंड ने ज्ञानदीप 2025 का आयोजन अजमेर रोड स्थित एक होटल में किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा जगत से जुड़े अनेक शिक्षकों और विद्वानों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे राजस्थान के शिक्षा मंत्री, मदन दिलावर तथा सीईओ एंड एडिटर एंड चीफ फर्स्ट इंडियन न्यूज, जगदीश चंद्र तथा अध्यक्ष, जयपुर व्यापार महासंघ, सुभाष गोयल और ओ.पी. अग्रवाल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। क्लब की अध्यक्ष ममता पंचोली, सचिव प्रीति सक्सेना, कोषाध्यक्ष अनुप्रा शर्मा, चार्टर मेंबर, सुधीर जैन, तेजेंद्र गर्ग और अजय अग्रवाल ने सभी अतिथियों और उपस्थित शिक्षकों का आभार व्यक्त किया और इस कार्यक्रम को ज्ञान व सम्मान की एक अविस्मरणीय संध्या बताया। कार्यक्रम में आर. एस. मदान, आलोक अग्रवाल, अशोक ज़िंदल, अजय डोगरा, पराग श्रीवास्तव, प्रवीण जैन और शुभम शर्मा की विशेष उपस्थिति रही। इस मौके पर शिक्षा जगत में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सुनीता बियोत्रा, डॉ. देवेंद्र कुमार शर्मा, इकबाल कुरेशी, जफर इकबाल, देवेंद्र कुमार भगत, गोविंद सैनी, निमिषा भट्ट, ममता शर्मा, डॉ. मोतू माथुर, डॉ. कल्पना रावत, प्रो. कनिका वर्मा, प्रो. रेशम बूलचंदानी, प्रो. शुभा दुबे, मीता माथुर, रेनु शर्मा, धीरज शर्मा, विमला कुमावत, डॉ. दीपा सचदेवा, डॉ. अनुराग प्रसाद, डॉ. दीपिका विजयवर्गीय, हेमलता शर्मा, डॉ. रीमा शाह, डॉ. दीपक शर्मा, प्रभा शर्मा, डॉ. पूरुष धवन सहित कई अन्य शिक्षकों को ज्ञानदीप सम्मान से नवाजा गया।



माननीय मुख्यमंत्री, बिहार नीतीश कुमार के साथ 07सितंबर 2025 को सिवान परिभ्रमण के अवसर पर पपौर में जनसभा स्थल का निरीक्षण करते हुए जिला पदाधिकारी सिवान एवं पुलिस अधीक्षक सिवान के साथ जिला के वरीय पदाधिकारी गण।

जीएसटी सुधारों से आम जनता को मिलेगा सीधा लाभ : मुनीश शर्मा
केंद्र सरकार का जताया आभार, बताया दूरदर्शी और जनहितैपी कदम

कैथल (कृष्ण प्रजापति): भाजपा जिला महामंत्री एवं जिला पार्षद मुनीश शर्मा फारन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी ढांचे में किए गए हालिया सुधार आम जनता और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभकारी साबित होंगे। उन्होंने इसे दूरदर्शी और जनहितैपी कदम बताया। सुनीश शर्मा ने कहा कि लगजरी कार, तंबाकू उत्पाद और शीतल पेय जैसी वस्तुओं को 40 प्रतिशत के उच्च स्लैब में रखकर सरकार ने स्वास्थ्य और सामाजिक संतुलन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है। इससे समाज में जिम्मेदार उपभोग की भावना को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन बदलावों का सकारात्मक असर जल्द ही देखने को मिलेगा। उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम होगा, व्यापारी वर्ग को कर अनुपालन में सरलता मिलेगी और कारोबार की नई गति मिलेगी। त्योहारों के मौसम से पहले लागू होने जा रहे ये सुधार उपभोक्ता मांग और उत्पादन दोनों को प्रोत्साहित करेंगे। युवा भाजपा नेता मुनीश शर्मा ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के ये कदम भारत को आर्थिक दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाएंगे और हरियाणा सहित पूरे देश के विकास की गति को तेज करेंगे।



प्रभारी मंत्री ने कांस्टेबल चालक संदीप शर्मा के घर पहुंच कर शोक व्यक्त किया



देश का दर्पण न्यूज,धौलपुर (धर्मेन्द्र बिद्यौलिया) 6 सितंबर। गृह राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेदम शनिवार को धौलपुर दौरे पर रहे। इस दौरान वह सड़क हादसे में मृत पुलिस कांस्टेबल चालक संदीप शर्मा के घर पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने कानि. संदीप शर्मा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर शोक व्यक्त किया। इस दौरान शोक संतप्त परिवार को ढाढस बांधते हुए उन्होंने कहा कि संदीप शर्मा हमारे परिवार के सदस्य था, उसकी कमी हमें महसूस होगी, उनके जाने के बाद हमारे परिवार के साथ खड़े हैं। इस दौरान जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी, पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने भी पुलिस कांस्टेबल चालक संदीप शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शोक व्यक्त किया।

कोहिनूर समिति ने किया दो दर्जन शिक्षकों का सम्मान



तिलक लगाकर उरपरणा पहनाकर व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया- विद्यालय संचालक अर्जुन देविलया, दिनेश छिपा, रामपाल शर्मा व तेज सिंह चौहान, कथा वाचक दीपा दाधीच, अध्यापिका सरोज शर्मा,शारदा प्रजापत, भगवती बाला पारीक, मोहनी शर्मा,मधुबाला दाधीच, अध्यापक आलोक त्रिपाठी, धर्मेन्द्र सिंह, राजेश पवार, मंजुला राजपूत, चंचल शर्मा, सुनीता गुर्जर,सुश्री संध्या सोनी,सुमन सोनी,विजेश पहाड़िया, रेखा बुनकर रिया शर्मा आदि को सम्मानित किया गया। नैनवा बूंदी से आए कवि बृज सुंदर परिवार को ढाढस बांधते हुए उन्होंने कहा कि संदीप शर्मा हमारे परिवार के सदस्य था, उसकी कमी हमें महसूस होगी, उनके जाने के बाद हमारे परिवार के साथ खड़े हैं। इस दौरान जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी, पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने भी पुलिस कांस्टेबल चालक संदीप शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शोक व्यक्त किया।

साइबर पुलिस ने दो ठगों को दबोचा, 2.15 लाख रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा

एजेंसी
नई दिल्ली । उत्तर-पूर्वी दिल्ली के साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो ठाों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को वित्तीय कंपनी का एक्जीक्यूटिव बताकर एक शख्स से 2,15,681 रुपए की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल अपराध में किया गया था। जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता वसीम (30), पुत्र रहींसुद्दीन, निवासी जोहरिपुर, जो गाजियाबाद में डेयरी व्यवसाय चलाते हैं, ने पुलिस को बताया कि 25 फरवरी 2025 को उन्हें एक व्यक्ति का कॉल आया। उसने खुद को एक नामी वित्तीय कंपनी का अधिकारी बताते हुए उन्हें लोन की पेशकश की, जिसके बाद वसीम लोन लेने के लिए राजी हो गए। ठाों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि लोन मंजूरी के लिए बीमा पॉलिसी खरीदना अनिवार्य है। इसके बाद उन्होंने वसीम के नाम से नामी बीमा कंपनियों की फर्जी पॉलिसियां जारी कीं और पॉलिसी शुल्क, बैंक चार्ज और लोन प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर उनसे बड़ी रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा ली। शिकायतकर्ता को कई बार पैसे देने के बावजूद कोई लोन उपलब्ध नहीं कराया गया।

दिल्ली: पॉक्सो केस का आरोपी को किया गिरफ्तार, चार बार जारी हुए थे गैर-जमानती वारंट

नई दिल्ली । दक्षिण-पश्चिम जिले के सरोजिनी नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने पॉक्सो केस में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी गौरव अम्नानी (32) की पहचान मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के ताड़िपुर मोरार निवासी के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ चार बार गैर-जमानती वारंट (गैर जमानती वारंट) जारी हो चुके थे, लेकिन वह लगातार कानून की प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहा था। जानकारी के मुताबिक, सरोजिनी नगर थाना क्षेत्र में फरार और वांछित आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सरोजिनी नगर थाने के इंस्पेक्टर अतुल त्यागी के नेतृत्व में हेड कॉन्स्टेबल हरिराम और कॉन्स्टेबल प्रवीण की टीम गठित की गई थी। एसीपी सफदरजंग एन्क्लेव की देखरेख में यह पूरी कार्रवाई की गई। 4 सितंबर को पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि पॉक्सो केस का एक आरोपी क्षेत्र में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और आरोपी गौरव अम्नानी को दबोच लिया। जांच में पता चला कि उसके खिलाफ पहले से ही कुल चार गैर-जमानती वारंट अलग-अलग पते पर जारी किए जा चुके थे।

दिल्ली: पहाड़गंज में स्कूल के बाहर चाकूबाजी मामले को पुलिस ने सुलझाया, 3 गिरफ्तार

नई दिल्ली । दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में स्कूल के बाहर चाकूबाजी की घटना को पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया। इस मामले में तीन नाबालिग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी उम्र 15 और 16 साल है। साथ ही, पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किए गए चाकू और घटनास्थल से टूटी हुई बोहरा की बोलत को बरामद किया। यह घटना 15 वर्षीय एक छात्र प्रहाड़गंज पुलिस स्टेशन पहुंचा, जिसके घटने में चाकू धंसा हुआ था। अपनी पहचान के साथ छात्र ने बताया कि स्कूल गेट पर कुछ छात्रों ने उस पर हमला किया था। इसके बाद, उसे तुरंत कलावती सरन अस्पताल पहुंचाया गया और बाद में आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने चाकू निकाला। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अपने बयान में घायल छात्र ने खुलासा किया कि आरोपी छात्र 'एस' अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पीटने का मौका तलाश रहा था। घटना वाले दिन जब वह स्कूल से निकल रहा था, आरोपी और उसके दो दोस्तों ने उसे स्कूल के गेट पर बुलाया और उससे झगड़ा करने लगे।

नालों की सफाई नहीं कराने पर बने बाढ़ जैसे हालात : केजरीवाल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केसरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने डिसिलिंग नहीं कराई जिससे दिल्लीवालों को बारिश के बाद तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्री केजरीवाल ने यहां सांथी पार्क में दिल्ली सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए लगाए गए राहत कैंपों का दौरा कर कहा कि दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तमाम इलाकों में पानी भर गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इन शिविरों में भी तमाम परेशानियां हैं, खाने और पानी तक का ठीक इंतजाम नहीं है। लोग बारिश के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया है, क्योंकि भाजपा सरकार ने डिसिलिंग नहीं कराई थी। इसलिए दिल्लीवालों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में भारी बारिश की वजह से तबाही हो रही है। केंद्र सरकार ने जैसे भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान के लिए राहत सामग्री भेजी, वैसे ही सरकार को इन राज्यों की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

माक़त-सिंगापुर ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप पर की चर्चा

एजेंसी
नई दिल्ली। भारत-सिंगापुर रक्षा कार्य समूह की 16वीं बैठक में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों के दौरान लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा के बाद दोनों पक्षों ने संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके समकक्ष लॉरेंस वॉंग के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद यह वार्ता सिंगापुर में हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप पर चर्चा हुई। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉंग तीन दिन की यात्रा पर 02 सितंबर को नई दिल्ली पहुंचे और गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके समकक्ष लॉरेंस वॉंग के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक को लेकर जारी संयुक्त वक्तव्य के बाद रक्षा कार्य समूह की 16वीं बैठक सिंगापुर में हुई। बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) अमिताभ प्रसाद और सिंगापुर रक्षा मंत्रालय के नीति कार्यालय के निदेशक कर्नल डैक्सन याप ने की। बैठक में पिछले रक्षा मंत्रियों की वार्ता और विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों के दौरान लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में रक्षा दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान करने और बहुआयामी द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करने वाली पहलों की गति तेज करने का फैसला लिया गया। दोनों पक्षों ने चल रहे रक्षा सहयोग पर संतोष

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यमुना के जलस्तर को लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ की बैठक

एजेंसी
नई दिल्ली। खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना के जलस्तर को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सभी जिलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर यमुना के जलस्तर और भारी बारिश की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 24×7 मॉनिटरिंग जारी रहे, राहत कार्य में कोई हिलाई न हो और हर दिल्लीवासी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो। उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी टीम सतर्क है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली में खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर बह रही यमुना का जलस्तर मामूली नीचे आया जो दोपहर एक बजे 207.22 मीटर दर्ज किया गया है। यमुना में

खतरे का निशान 205.33 है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार गुरुवार से यमुना के जलस्तर में

88462 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हालांकि यमुना से सटे इलाके पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहे हैं।



गिरावट दर्ज की गई है। दोपहर एक बजे जलस्तर 207.22 मीटर पर दर्ज किया गया है। इस दौरान हरियाणा के हथिनी कुंड बांध से

जल भराव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना किनारे बसे लोग अपने पशुओं को लेकर सड़कों पर बस गए

ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ प्रदर्शन पर भारत ने जताई चिंता

एजेंसी
नई दिल्ली। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में हुए एंटी-इमिग्रेंट (प्रवासन के खिलाफ) प्रदर्शनों पर चिंता जताई है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत चिंताओं का संज्ञान लेते हुए माना है कि यह प्रदर्शन उनके बहुसांस्कृतिक समाज के लिए चिंता का विषय हो सकता है। भारत ने आश्वासन दिया है कि वह विदेश में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ हल ही में हुए प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता ने कहा कि 31 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में एंटी-इमिग्रेंट प्रदर्शन हुए। इस दौरान भारत का उच्चायोग और महावाणिज्य दूत लगातार ऑस्ट्रेलियाई सरकार और भारतीय समुदाय के संपर्क में रहे। जायसवाल ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार और विपक्ष



भारतवशियों ने ऑस्ट्रेलिया की तरक्की और विकास में अहम भूमिका निभाई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत विविधता को ताकत मानता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक

रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें लोगों के बीच का जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। यही आपसी संबंध दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत सरकार

विदेश में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। इस सिलसिले में भारत लगातार ऑस्ट्रेलियाई सरकार और वहां के प्रवासी संगठनों के संपर्क में है।

पीएमएवाई-यू 2.0: केंद्र ने शहरी आवासों के निर्माण में तेजी लाने को थुरु किया अंगीकार अभियान

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शहरों में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को पक्का घर देने के लिए 'अंगीकार 2025' अभियान शुरू किया है। यह अभियान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के तहत हो रहे घरों के निर्माण में तेजी लाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में विधवाओं, एकल महिलाओं, किशोरों, बुजुर्गों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जाति और जनजाति, अल्पसंख्यकों, सफाई कर्मियों, सड़क पर दुकान लगावे वालों, आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को पक्का घर बनाने या खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी। साथ ही उन्हें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का फायदा भी मिलेगा। इस अभियान के तहत कम आय वाले लोगों को ऋण जोखिम गारंटी निधि के बारे में भी बताया जाएगा। अभियान का शुभारंभ करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि अंगीकार 2025 सरकार की उस सोच को दिखाता है, जो गरीबों और कमजोर वर्गों तक मदद पहुंचाने की है। यह अभियान दूसरी योजनाओं के साथ मिलकर देश का विकास करेगा। यह सबके लिए घर के सपने को पूरा करने का बड़ा कदम है। यह अभियान 4 सितंबर से 31 अक्टूबर तक देश के 5 हजार से ज्यादा शहरों

और कस्बों में चलेगा। इसमें घर-घर जाकर लोगों को बताया जाएगा, ऋण मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उन्हें जोड़ा जाएगा।

पीएमएवाई-यू के तहत अब तक 120 लाख घरों को मंजूरी मिली है, जिनमें 94.11 लाख घर बनकर लोगों को दिए जा चुके हैं। अंगीकार 2025 अभियान से बाकी बचे घरों को जल्दी पूरा करने में मदद मिलेगी। इसी साल 17 सितंबर को पीएमएवाई-यू 2.0 की पहली सालगिराह पर आवास दिवस भी मनाया जाएगा। साथ ही 17 से 27 सितंबर और 16 से 31 अक्टूबर के बीच दो चरणों में जिला मुख्यालयों और बड़े शहरों में पीएम आवास मेला-शहरी का आयोजन भी होगा। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2024 में शुरू हुई पीएमएवाई-यू 2.0 का लक्ष्य

अगले पांच साल में एक करोड़ और घर बनाना है। यह योजना चार तरह से काम करती है। लाभार्थी खुद घर बनाएँ, साझेदारी में सस्ते घर, किराए के सस्ते घर और ब्याज पर छूट। हाल ही में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 2.35 लाख घरों को मंजूरी मिली, जिनमें 1.25 लाख से ज्यादा महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए है। शुभारंभ के मौके पर राज्यमंत्री तोयन साहू, मंत्रालय के सचिव निवास कटिचितला, संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण और कई अधिकारी मौजूद थे। कुलदीप नारायण ने राज्यों के अधिकारियों के साथ मिलकर अभियान को सफल बनाने की योजना के बारे में भी बताया।

जेपी नड्डा ने एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी रद्द की, पंजाब समेत दूसरे राज्यों में बाढ़ के हालात को देखते हुए फैसला

एजेंसी
नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आवास पर आयोजित होने वाली एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी को रद्द कर दिया है। यह निर्णय पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए लिया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर शनिवार को एनडीए सांसदों के लिए 'डिनर' पार्टी होनी थी। डिनर का आयोजन उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर किया जाना था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल होना था। फिलहाल, जानकारी सामने आई है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से इस आयोजन को रद्द करने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि 'इंडिया' ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। उपराष्ट्रपति चुनाव जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हो रहे हैं। 21 जुलाई की रात को जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल, संख्या के लिहाज से एनडीए के सीपी राधाकृष्णन अपने प्रतिद्वंद्वी और 'इंडिया' ब्लॉक के उम्मीदवार न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी पर अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में कुल 245 सदस्यों में से 233 सांसद हैं। भाजपा के निचले सदन में 240 और उच्च सदन में 102 सांसद हैं। वाईएसआरसीपी (11 सांसद) ने पहले ही एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा कर दी है, जिससे राधाकृष्णन के समर्थन की संख्या 433 तक पहुंच गई है, जो कि निर्णायक बहुमत है।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा की उपेक्षा का आरोप लगाया

संकट सरकार की मनरेगा को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। पिछले 11 सालों से मनरेगा को



पर्याप्त बजट नहीं मिला और महंगाई के बावजूद तीन साल से इसका बजट स्थिर है। इससे मांग-आधारित योजना का मकसद कमजोर हुआ है और लाखों मजदूरों को जरूरत के समय काम नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना के तहत मजदूरी भुगतान में देरी आम है जिसमें 15 दिन की वैधानिक समयसीमा का पालन

नहीं होता। हर साल बजट का 20-30 फीसदी हिस्सा पिछले बकाये चुकाने में खर्च होता है और मुआवजा भी नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि 11 सालों में इस योजना के तहत मजदूरी में मामूली वृद्धि हुई जिससे आय का संकट बढ़ा है। सरकार ने पारदर्शिता के नाम पर नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एमएमएमएस) ऐप और आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) लागू की जिसके कारण करीब 2 करोड़ मजदूरों को काम और भुगतान नहीं मिला। कांग्रेस महासचिव रमेश ने मांग की कि मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए और मजदूरी समय पर दी जाए। योजना के तहत न्यूनतम मजदूरी 400 प्रतिदिन करने और मजदूरी दर तय करने के लिए स्थायी समिति बनाए जाने की मांग की। उन्होंने केन्द्र से एएमएमएस और एबीपीएस जैसी प्रणालियों को अनिवार्य करने पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया।

पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का करेंगे दौरा, राहत कार्यों का लेंगे जायजा

एजेंसी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित उत्तर भारत के कई राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो बाढ़ प्रभावित राज्यों में स्थिति की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा लगातार बारिश से हुई तबाही के बीच हो रहा है, जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है और बुनियादी ढांचे और कृषि को भारी नुकसान पहुंचाया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के कारण इस मौसम में 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले दो दिनों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और मकान ढहने से दर्जनों लोगों की जान चली गई है। राजमार्ग अवरुद्ध हैं, नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं और हजारों लोग फंसे हुए हैं क्योंकि यह क्षेत्र दशकों में सबसे खराब मौसम आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक बना हुआ है, जहां मानसून की शुरुआत से अब तक 360 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के अनुसार, 1,087 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 2,838 बिजली आपूर्ति लाइनें और 509 जल आपूर्ति योजनाएं बाधित हैं। अनुमान के मुताबिक 3,979.52 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है, जिससे सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के बुनियादी ढांचे प्रभावित हुए हैं।

यमुना के जलस्तर में गिरावट जारी, बाढ़ से प्रभावित फसलों के आकलन का निर्देश : रेखा गुप्ता

एजेंसी
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना के जलस्तर में फिलहाल गिरावट जारी है और दिल्ली वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। यमुना का जलस्तर सात बजे 207.09 दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह खुद हालात पर लगातार निगरानी रख रही है और प्रशासन बाढ़ प्रभावितों की 24×7 मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि राहत शिविरों में भोजन, पानी, चिकित्सा, शौचालय सुविधाओं के अलावा जरूरी मदद लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। अधिकारियों को बाढ़ से प्रभावित फसलों का आकलन करने का निर्देश दिया गया है।राजधानी में बाढ़ की स्थिति, प्रभावित क्षेत्रों के हालात और पीड़ितों को जरूरी मदद को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कैप कार्यालय चमुख्यमंत्री जनसेवा सदन' से डिविजनल कमिश्नर व सभी जिलों के डीएम के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की और जरूरी व स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक को

जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुना में बाढ़ का पानी लगातार कम हो रहा है और संभव है कि हालात जल्द सामान्य हो जाएं। इसके

जान-माल की रक्षा करना हमारी सरकार का प्रमुख दायित्व है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि



बावजूद हमारी सरकार बाढ़ प्रभावितों की लगातार मदद में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि सभी वरिष्ठ अफसरों को कहा गया है कि वे बाढ़ से प्रभावित इलाकों में चौबीस घंटे निगरानी रखें और राहत शिविरों में भोजन, पानी, चिकित्सा, शौचालय व अन्य जरूरी सेवाओं का उचित प्रबंध करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों की

लगातार बारिश के कारण यमुना में आई बाढ़ के कारण नदी के निचले इलाकों में बसे लोगों को वहां से हटाना पड़ा। इसी सरकार ने इन बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत शिविरों का इंतजाम किया है और वहां उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी डीएम को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं बाढ़ प्रभावित बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों का विशेष ध्यान

रखा जाए। मुख्यमंत्री के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी रख रहा है। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यकता पड़ने पर वे क्षेत्र के सामाजिक संठठनों की भी मदद लें ताकि बाढ़ प्रभावितों को त्वरित व समय पर मदद मिल सके। सभी डीएम को यह भी निर्देश दिए गए हैं बाढ़ प्रभावित किसानों के मवेशियों व अन्य जानवरों को बाढ़ से सुरक्षित रखा जाए और उनके चारे आदि की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकारी अमला प्रभावित इलाकों की लगातार निगरानी कर यह सुनिश्चित कर रहा है कि किसी प्रकार की गंभीर नुकसान से बचा जा सके। यही हमारी सरकार का नैतिक व प्रशासनिक दायित्व है। उन्होंने डीएम को यह भी निर्देश जारी किए हैं कि वे बाढ़ से प्रभावित फसलों का भी आकलन करें ताकि उन्हें पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा देने पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जा सके।

एजेंसी
नई दिल्ली। कांग्रेस की केरल प्रदेश इकाई द्वारा बिहार की तुलना बीड़ी से करने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे राज्य के लोगों का अपमान बताया है। भाजपा ने मोदी सरकार के जीएसटी सुधारों का विरोध करने के लिए केरल कांग्रेस द्वारा किए

गए इस एक्स पोस्ट को बिहार विरोधी करार देते हुए प्रदेश को बुद्ध की भरती और अखंड भारत का निर्माता बताया। हालांकि इस प्रकरण पर विवाद बढ़ता देख केरल कांग्रेस ने पोस्ट डिलीट का दिया और माफी भी मांग ली। भाजपा प्रवक्ता शहजाद मुतावाला ने कहा कि कांग्रेस ने पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

की मां को गाली दी और अब बिहार को बीड़ी से जोड़ा। उन्होंने कहा कि क्या तेजस्वी यादव इस अपमान का समर्थन करते हैं? तेलंगाणा के मुख्यमंत्री रवंत रेड्डी, डीएमके और कांग्रेस की बिहार के प्रति नजरत साफ दिखती है।भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस और राजद बिहार विरोधी है।

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पहले भी बिहारियों का अपमान करने वालों का साथ दिया है।बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस पोस्ट पर उतर आई है और बिहार की जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री जोतन राम मांझी के बयान पर भाजपा नेता ने कहा कि बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है और सभी सहयोगी दल मिलकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।

कहा कि भारत की जनता लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देगी।पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस कितना नीचे गिर सकती है, पहले प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान हुआ, अब बिहार की तुलना बीड़ी से की गई। उन्होंने राहुल गांधी से जवाब मांगा और कहा

कि बिहार के गौरव का अपमान बदरत नहीं होगा।केरल भाजपा के महामंत्री अनूप एंटनी जोसेफ ने कहा कि कांग्रेस ने बुद्ध की धरती बिहार को बीड़ी से जोड़कर अपमान किया। उन्होंने बिहारवासियों से अपील की कि वे इस अपमान को वोट के जरिए याद रखें।बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय

कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार ने अखंड भारत का निर्माण किया और ज्ञान-विज्ञान की भूमि रहा है। इस अपमान का जवाब बिहार की जनता दौड़-जानता दल यूनास्टेड (जदयू) सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि बी से सिर्फ बीड़ी नहीं, बुद्धि और बजट भी होता है, जो कांग्रेस के पास

नहीं है। उन्होंने बिहार की गौरवशाली विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि यह मां जायकी, बुद्ध, सम्राट अशोक और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की धरती है। बिहार ने गांधी को राष्ट्रपिता बनाया और संपूर्ण क्रांति के जरिए कांग्रेस की तानाशाही को उखाड़ फेंका।

संपादकीय

एक जैसे दिखने वाले नाशापाती और बब्बूगोशा में क्या-क्या है फर्क, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी जानें



मौसम के हिसाब से मार्केट फल आते रहते हैं. जो स्वाद में तो लाजवाब होते हैं। हैं. साथ

ही शरीर को कई तरह के न्यूट्रिन भी देते हैं. इस तक बाजार में नाशापाती और बब्बूगोशा काफी देखने को मिल रहा है, जो दिखने कुछ हद तक एक जैसे लगते हैं, लेकिन न्यूट्रिन के मामले में दोनों काफी अलग हैं.

फल हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं. इनमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं. हर मौसम में अलग-अलग फल आते हैं, जिन्हें लोग अपनी डाइट में शामिल करते हैं. जैसे गर्मियों में आम, तरबूज और खरबूजा खूब खाया जाता है. वहीं, बरसात में अमरूद, नाशापाती और बब्बूगोशा मार्केट में छाया रहता है. नाशापति और बब्बूगोशा दो ऐसे फल हैं, जो दिखने में एक जैसे लगते हैं. जब भी बाजार में ये दो फल आते हैं तो कुछ लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं. दोनों का हल्का हरा रंग, बनावट और यहाँ तक की दाम भी कभी-कभी मिलता-जुलता होता है.

लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अलग ही होते हैं. वहीं, स्वाद के मामले में भी नाशापाती और बब्बूगोशा में काफी अंतर होता है. चलिए आज इस आर्टिकल में जानते हैं एक जैसे दिखने वाले नाशापाती और बब्बूगोशा के न्यूट्रिन वैल्यू में कितना फर्क है और सेहत के लिहाज से कौन सा फल ज्यादा बेहतर है.

नाशापाती और बब्बूगोशा में ये है अंतर

नाशापाती को अंग्रेजी में ब्रह्मह्र के नाम से जाना जाता है. जबकि बब्बूगोशा को देसी माना जाता है. दोनों के अंग्रेजी में सर्च करने पर ब्रह्मह्र ही दिखाता है. नाम एक जैसे होने की वजह से भी कई लोग इसमें कंप्यूज हो जाते हैं. हालांकि, इनमें कुछ अंतर होता है. जैसे नाशापाती का ऊपर का छिन्का हार्ड होता है, वहीं बब्बूगोशा का छिलका सॉफ्ट होता है. टेस्ट की बात करें तो नाशापाती रसीली तो होती है लेकिन इसमें हल्का सा कड़वा स्वाद में आता है. लेकिन दूसरी तरफ बब्बूगोशा स्वाद में काफी मीठा और रसीला होता है. इसका गूदा सॉफ्ट होता है.

नाशापाती और बब्बूगोशा के न्यूट्रिन

नाशापाती के पोषक तत्वों की बात करें तो, इसमें फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. इसके अलावा ये विटामिन सी, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम और एंथोसायनिन भी पाया जाता है. फाइबर होने की वजह से ये वजन कंट्रोल करने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. साथ ही शरीर को इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट पाचन को बेहतर बनाता है.

दूसरी तरफ बब्बूगोशा की बात करें तो इसमें भी फाइबर पाया जाता है. इसके अलावा विटामिन छ, विटामिन च, पोटेशियम और फ्लेवोनोइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. ये पाचन के लिए बेहतर है. बब्बूगोशा में पानी की मात्रा में अच्छी होती है, ऐसे में ये शरीर को हाईड्रेट रखने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन माना जाता है.

सेहत के लिए कौन है बेहतर ?

नाशापाती और बब्बूगोशा दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. दोनों ही फलों में अच्छी खासी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं. फाइबर के लिए नाशापाती और बब्बूगोशा दोनों ही अच्छे सोर्स हैं. जो वजन कंट्रोल करने से लेकर पाचन बेहतर करने में लाभकारी हैं. हालांकि, नाशापाती में बब्बूगोशा के मुकाबले ज्यादा कैलोरी होती है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों में से किसी भी फल को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

भारत पर अधिकतम 50 प्रतिशत टैरिफ

लगाने के अलावा अमेरिका ने दुनिया

के लगभग 67 देशों पर व्यापार टैरिफ

लगाया है

भारत पर अधिकतम 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के अलावा अमेरिका ने दुनिया के लगभग 67 देशों पर व्यापार टैरिफ लगाया है। व्यापार शुल्कों में यह वृद्धि और कमी भारत के विरुद्ध एक सुनियोजित लेन-देन के रूप में देखी जा सकती है। स्पष्ट है, डोनाल्ड ट्रंप भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। भारत पर अमेरिकी व्यापार शुल्कों का प्रभाव बहुत बड़ा होगा

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से जारी शीतयुद्धकी समाप्ति ने अमेरिका को विश्व की एकमात्र शक्ति बना दिया था। दुनिया के लगभग सभी देश अमेरिका के इर्द-गिर्द प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे थे। इस अवसर का लाभ उठाकर अमेरिका ने अपने पूंजी बाजार का विस्तार और पूरी दुनिया में पूंजीवाद को सक्रिय करने का प्रयास किया।

अमेरिका के उकसावे पर %विश्व व्यापार संगठन% (डब्ल्यूटीओ) ने दुनियाभर में व्यापार का विस्तार करके अमेरिकी पूंजी बाजार को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत करने का असफल प्रयास किया था। व्यापार के आधार पर दुनिया के बंट जाने से अमेरिका के हितों को भारी नुकसान पहुंचा। शीतयुद्ध में सोवियत संघ अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरा था, लेकिन बाद में रूस, चीन और जापान जैसी महाशक्तियां अमेरिका के सामने आईं। भारत, इजरायल और ब्राजील भी विकासशील देशों की सूची से उठकर विकसित देशों की दौड़ में शामिल हो गए। ऐसे में अमेरिका का नेतृत्व दुनिया में काफी हद तक अप्रभावी होता गया।

इसी तरह पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बाद ईरान को परमाणु शक्ति-संपन्न देशों की सूची में शामिल करने से अमेरिका का प्रभाव दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। जब व्यापार ने दुनिया को कई क्षेत्रों में बांट दिया है और इसके कारण अमेरिकी पूंजी बाजार को व्यापक नुकसान पहुंच रहा है, तब अमेरिका असहिष्णु हो गया है। इसी असहिष्णुता के परिणामस्वरूप अमेरिका ने अपने आयातों को लेकर पूरी दुनिया को फिर से एक क्षेत्र में बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां दुनिया के

असहिष्णुता है, 'टैरिफ युद्ध' की वजह



कई देशों पर व्यापार कर (टैरिफ) बढ़ाकर उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं वे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके अमेरिका को फिर से दुनिया का नंबर एक देश बनाने का सपना देख रहे हैं। इसी वजह से वे अमेरिका को फिर से महान बनाओ (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा) का आह्वान कर रहे हैं।आज व्यापार पूरी दुनिया के देशों, उनकी अर्थव्यवस्थाओं और करोड़ों लोगों को नियंत्रित कर रहा है। देशों के बीच व्यापार आधारित असहिष्णुता फैल रही है। विशेष रूप से अमेरिका इस असहिष्णुता का शिकार हुआ है और इसके परिणामस्वरूप विश्व में एक नया युद्ध शुरू हो गया है, जिसे कई लोग टैरिफ युद्ध या व्यापार युद्ध का नाम दे रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल में 2018 से 2021 के बीच कुछ क्षेत्रों में टैक्स लगाए थे। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप 2025 से व्यापार-करो पर अधिक ध्यान दे रहे हैं और अमेरिका को फिर से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने, अमेरिकी सीमा की सुरक्षा, कनाडा और मेक्सिको के साथ संघर्ष को समाप्त करने, विश्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने, परमाणु युद्ध की भयावहता से बचने आदि की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे कर-युद्ध फांद रहे हैं; लेकिन

संपादकीय

राहतकारी जीएसटी



जरिये घरेलू उपभोग व निवेश को बढ़ाया जाए। निस्संदेह, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। यही वजह है कि कुछ अर्थशास्त्री जीएसटी दरों को घटाने को साहसी व दूरदर्शी कदम बताते हैं, जो उपभोक्ता के उपभोग को बढ़ाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने एक जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू किया था। उसके बाद समय-समय पर विभिन्न उत्पादों की दरों में परिवर्तन किए जाते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों द्वारा शासित सरकारें कई

उत्पादों पर जीएसटी दरें तार्किक बनाने की मांग करती रही हैं। जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर घटाने की मांग की थी। इतना ही नहीं, कुछ उद्योगों, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों व जन-स्वास्थ्य से जुड़ी वस्तुओं के उत्पादकों द्वारा जीएसटी कम करने की मांग की जाती रही है। इसी तरह किसान संगठन भी कृषि उत्पादों पर कर कम करने की मांग करते रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर जीएसटी दरों में बदलाव की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। उनका मानना है कि इसकी पृष्ठभूमि में ट्रंप के टैरिफों को कम करने की कवायद भी है ताकि घरेलू उपभोग बढ़ाया जा सके और सस्ते निर्यात को बढ़ावा मिल सके। कालांतर इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल सकेगी। इसका संकेत प्रधानमंत्री ने पंद्रह अगस्त को लाल किले से संबोधन में भी दिया था। वहीं आगामी वर्ष मार्च में राज्यों को राहत देने वाले कम्पेंसेशन सेस की समाप्ति से पहले राज्यों को राहत देने के लिये भी यह

कदम उठाया गया हो सकता है। निस्संदेह, इस कदम से सरकारी खजाने में जीएसटी कम आएगा, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि विलासिता की वस्तुओं पर चालीस फीसदी का जीएसटी सरकार के घाटे की पूर्ति में किसी हद तक मदद करेगा। फिर भी कहा जा रहा है कि सरकार को अड़तालीस हजार करोड़ का नुकसान हो सकता है, लेकिन चीजें सस्ती होने पर उपभोग वृद्धि से सरकार को राहत मिल सकती है। वहीं कहा जा रहा है कि असंगठित क्षेत्र को जीएसटी कटीती दक का लाभ नहीं मिलेगा। अर्थशास्त्री लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले असंगठित क्षेत्र को आर्थिक सुधारों का लाभ दिया जाना चाहिए। बहरहाल, इतना तय है कि जीएसटी दरों में कमी से उपभोक्ता मांग में वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। आम आदमी कम पैसे में ज्यादा सामान खरीद पाएगा। वैसे यहां यह बात महत्वपूर्ण है कि इस बदलाव से वास्तव में आम उपभोक्ता को कितना फायदा होता है।

लगातार अनिश्चित हो रही विधेयकों के अनुमोदन की समय-सीमाएं

इस अनिश्चितता के व्यावहारिक परिणाम दूरगामी हैं। यदि 8 अप्रैल का फैसला बरकरार रहता है, तो राज्यपालों और राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिससे पूर्वानुमानितता पैदा होगी और विधायी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। फिर भी, ऐसा करने से, यह उस विचार-विमर्श की गुंजाइश को भी कम कर देता है ।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा राज्यपालों और राष्ट्रपति को उनके पास भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित तीन महीने की समय-सीमा, जिसकी अब मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा पुनर्परीक्षा की जा रही है, लगातार अनिश्चित होती जा रही है। यह मामला, जो मूल निर्णय के समय सुलझा हुआ प्रतीत हो सकता था, अब नाजुक होता जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति के संदर्भ की सुनवाई के माध्यम से व्यापक संवैधानिक सिद्धांत सामने आ रहे हैं। दो-न्यायाधीशों के निर्णय की स्थिरता अनिश्चित प्रतीत होती है, न केवल बड़ी पीठ के संदेह के कारण, बल्कि अप्रैल के निर्णय में निहित अस्पष्टताओं के कारण भी, जो अपेक्षित परिणामों के द्वार खुले छोड़ देती हैं। दांव पर केवल विधायी प्रक्रियाओं की दक्षता ही नहीं, बल्कि संवैधानिक पाठ, न्यायिक रचनात्मकता और अनजाने में नए संवैधानिक मानदंडों के निर्माण के जोखिमों के बीच संतुलन भी है।

शुरू से ही, 8 अप्रैल के इस फैसले की कुछ हलकों में राज्यपालों द्वारा रखानेसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोकें रखने की लगातार शिकायतों के समाधान के रूप में सराहना की गई। राज्यपालों और राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर निर्णय लेने के लिए अनिवार्य करने वाले इस आदेश को जवाबदेही बढ़ाने और कार्यपालिका की मनमानी को रोकने के रूप में देखा गया। हालांकि, इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप प्रतीत होता था, लेकिन इसमें अपनाई गई विधि, जो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं, एक कठोर समय-सीमा लागू करना-समस्याओं से भरी थी।अब राष्ट्रपति के संदर्भ पर विचार कर रही बड़ी पीठ ने पहले ही इस तनाव को चिह्नित कर दिया है और आगाह किया है कि समय-सीमा अनिवार्य करना वास्तव में संविधान में संशोधन के समान हो सकता है। यह तक इस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है कि दस्तावेज़ के निर्माताओं ने, व्यापक बहस के बाद, संबंधित कार्यकारी प्राधिकारियों पर ऐसी सख्तियां लागू करने से जाबजूद कर परहेज़ किया

था। इसके बजाय, उन्होंने दुरुपयोग को रोकने के लिए असाधारण मामलों में परंपराओं, राजनीतिक जिम्मेदारी और न्यायिक निगरानी पर भरोसा किया। एक निश्चित अवधि को संवैधानिक मौन मानने का प्रयास करके, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने शायद एक ऐसी सीमा पार कर ली है जिसे नेकनीयत न्यायिक नवाचार भी उचित नहीं ठहरा सकते।

बड़ी पीठ ने एक सूक्ष्म दृष्टिकोण व्यक्त किया है। यह असाधारण विलंब के मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप की वैधता को स्वीकार करता है, जहां सहमति न देना या निष्क्रियता स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक इच्छाशक्ति को नष्ट करती है। ऐसा हस्तक्षेप उपचारात्मक है, जिसका उद्देश्य संवैधानिक विघटन के विशिष्ट उदाहरणों को संबोधित करना है। हालांकि, इस मामले में विशिष्ट उपाय को हर स्थिति में लागू होने वाले एक सार्वभौमिक नियम में परिवर्तित करने से वैचारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इससे न्यायपालिका के लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से पुनर्लेखन करके एक विधायी कार्य संभालने का जोखिम पैदा होता है। पीठ की आशंका है कि ऐसा दृष्टिकोण संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर सकता है, क्योंकि यह भविष्य में न्यायिक रूप से निर्धारित समय-सीमाओं को चुनौती देने वाले मुकदमों की संभावना को खुला छोड़ देता है, जिससे समाधान के बजाय अंधक अस्थिरता पैदा होती है।8 अप्रैल के फैसले में न्यायिक समीक्षा के अपने व्यवहार में भी अस्पष्टताएं हैं। इसने सही ही पृष्ठ की कि विधेयकों को लंबित रखने में राज्यपाल का आचरण न्यायिक जांच से परे नहीं है। यह कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है कि कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी जवाबदेही से मुक्त नहीं है, खासकर जब निष्क्रियता प्रतिनिधि लोकतंत्र को कमजोर करती है। फिर भी, यह निर्णय ऐसी समीक्षा के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में विफल रहा।विशेष रूप से, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या जांच केवल आखरण तक ही सीमित है-अर्थात विलंब तक-या क्या यह विधेयकों के सार को भी शामिल कर सकती है। निर्णय यह सुझाव देता प्रतीत होता है कि एक बार जब किसी विधेयक को निर्धारित अवधि बीत जाने के कारण स्वतः स्वीकृति मिल जाती है, तो राज्यपाल की पूर्ण निष्क्रियता को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन क्या इससे संबंधित विधेयकों की विषयवस्तु, आचार्य और संवैधानिक वैधता की भी जांच करने का रास्ता खुलता है? यदि बिना किसी टोस समीक्षा के स्वतः स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, तो संभावना है कि सदिष्ट संवैधानिक योग्यता वाले विधेयक



बिना किसी जांच के पारित हो सकते हैं। इसके विपरीत, यदि न्यायालय स्वयं विषयवस्तु की जांच में शामिल होते हैं, तो यह न्यायिक वीटो के समान हो सकता है, जो शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर करता है।

इन विवादों को सुलझाने के लिए स्पष्ट संस्थागत रास्तों के अभाव से दुविधा और भी जटिल हो जाती है। संविधान में नियंत्रण और संतुलन की एक ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की गई है जहां राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में, राज्य के विधानों में संवैधानिक औचित्य की रक्षा में एक सीमित लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, विधेयकों पर अनिश्चित काल तक रोक लगाकर इस पद का दुरुपयोग करने से यह सुरक्षा अवरोध का साधन बन गया है। इस असंतुलन को दूर करने की न्यायपालिका की प्रवृत्ति समझ में आती है, लेकिन एक कठोर ढांचा लागू करके, अप्रैल के फैसले ने एक और संतुलन- न्यायिक व्याख्या और संवैधानिक संशोधन के बीच की रेखा- को बिगाड़ने का प्रयास किया। वृहद पीठ की चिंता, सुविधावाद की आड़ में न्यायिक अतिक्रमण के खतरे को उजागर करती है।इस अनिश्चितता के व्यावहारिक परिणाम दूरगामी हैं। यदि 8 अप्रैल का फैसला बरकरार रहता है, तो राज्यपालों और राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिससे पूर्वानुमानितता पैदा होगी और विधायी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। फिर भी, ऐसा करने से, यह उस विचार-विमर्श की गुंजाइश को भी कम कर देता है जिसका संविधान निर्माताओं ने इरादा किया होगा, खासकर उन मामलों में जहां विधेयक जटिल संवैधानिक या नीतिगत प्रश्न उठाते हैं।

दूसरी ओर, यदि वृहद पीठ द्वारा फैसले को खारिज कर दिया जाता है, तो अनिश्चितकालीन विलंब की यथास्थिति वापस आ जाएगी, जब तक कि संसद स्वयं समय-सीमा तय करने के लिए हस्तक्षेप न करे, जो एक राजनीतिक रूप से जटिल प्रस्ताव है। किसी भी स्थिति में, गहरा सवाल अनसुलझा रहता है- जब विधेयकों में देरी हो रही हो, तो न्यायिक समीक्षा का वैध दायरा क्या होना चाहिए? क्या न्यायपालिका केवल यह आकलन करने तक सीमित है कि क्या देरी अनुचित है, या क्या वह आगे बढ़कर विधेयकों की प्रकृति की जांच कर सकती है, जब तक कि स्वीकृति न मिल जाए?

अप्रैल के फैसले में स्पष्टता की कमी से मुकदमों की बाढ़ आने का खतरा है। उदाहरण के लिए, तीन महीने की राज्यपालीय चुप्पी के बाद स्वतः कानून बन जाने वाले किसी विधेयक को बाद में संवैधानिक कमजोरियों के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। तब अदालतों को न केवल स्वतः स्वीकृति तंत्र की वैधता पर, बल्कि स्वयं कानून की मूल संवैधानिकता पर भी निर्णय लेने के लिए कहा जाएगा। यह दो-स्तरीय मुकदमेबाजी उस निश्चितता को प्रदान करने के बजाय जटिलता की परतें बढ़ाएगी जिसका दावा इस फैसले में किया गया था। यह राज्यपालों को रणनीतिक रूप से पीछे हटने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकता है, यह जानते हुए कि विवादास्पद विधेयक, एक बार स्वतः स्वीकृति मिलने के बाद, वैसे भी न्यायिक बाधाओं का सामना करेंगे। ऐसा परिणाम विरोधाभासी रूप से उसी समस्या को और मजबूत कर सकता है जिसका समाधान अप्रैल के फैसले में किया गया था।

बड़ी पीठ के समक्ष चल रही सुनवाई इन तनावों को दूर करने की कठिनाई को रेखांकित करती है। न्यायिक रचनात्मकता लंबे समय से भारतीय संवैधानिक कानून की एक पहचान रही है, मूल संरचना सिद्धांत से लेकर मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्याओं तक। फिर भी, व्याख्या और संशोधन के बीच एक रेखा, चाहे कितनी भी धुंधली क्यों न हो, रही है। 8 अप्रैल के फैसले पर बहस उस सीमा की नाजुकता को उजागर करती है। समय-सीमाएं निर्धारित करके, दो न्यायाधीशों की पीठ ने हमें ही नेकनीयती से प्रयास किया हो, शायद हद पार कर दी हो। बड़ी पीठ का सतर्क दृष्टिकोण इस जागरूकता को दर्शाता है कि संवैधानिक मौन का सम्मान किया जाना चाहिए, भले ही वे कभी-कभी कार्यपालिका के अवरोधों की अनुमति देते हों।

व्यापार

शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 13 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची

एजेंसी
नई दिल्ली। वैश्विक दबाव और टैरिफ संबंधी आशंकाओं की वजह से विदेशी निवेशक इस साल लगातार घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली करके अपना पैसा निकालने में लगे हुए हैं। इस वजह से बाजार में उनकी हिस्सेदारी भी लगातार कम हो रही है। अगस्त के महीने में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी घटकर 13 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी अभी तक सबसे ऊंचे स्तर पर है। नेशनल सिक्वेरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के आंकड़ों के अनुसार अगस्त के महीने में विदेशी निवेशकों की गई बिकवाली के चलते अब भारतीय शेयर बाजार में फॉरेन पोर्टफोलियो असेट्स 70.33 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर आ गए हैं, जबकि 1 महीने पहले भारतीय शेयर बाजार में फॉरेन पोर्टफोलियो असेट्स 71.97 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर थे। यानी आगस्त के महीने में इसमें लगभग 2.30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार अगस्त के महीने के अंत तक विदेशी निवेशकों के हिस्सेदारी भारतीय शेयर बाजार में घटकर 15.85 प्रतिशत रह गई है। विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी जहाँ लगातार घट रही है, वहीं भारतीय शेयर बाजार में घरेलू संस्थागत निवेश को हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई है।

लेज ने चमिंदी की चिढ़ी’ पहल के जरिए भारतीय किसानों को किया सम्मानित, स्पेशल पैक किए लॉन्च

नई दिल्ली। पेप्सिको इंडिया के पोटेटो चिप्स ब्रांड्स लेज ने भारतीय किसानों के चित्रों वाली एक सीमित-संस्करण पैक लॉन्च किए हैं। ये पैक आलू उगाने वालों और उन्हें खाने वालों के बीच के संबंध को उजागर करते हैं। सीमित समय के लिए चुनिंदा बाजारों में उपलब्ध ये लिमिटेड एडिशन क्लासिक साल्टेड पैक अब देशभर के रिटेल स्टोर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इसकी कीमत 50 रुपये है। लेज ने मिट्टी से मुस्कान तक की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहली बार लिमिटेड एडिशन पैक पेश किया है। इस पैक में भारतीय किसानों को दर्शाया गया है। लेज ने अपने प्रतिष्ठित पैक को एक कहानी कहने वाले केनवास में बदल दिया है, जिससे आलू उगाने वाले किसानों और उन्हें खाने वाले उपभोक्ताओं के बीच जुड़ाव और गहरा हो गया है। प्रत्येक पैक उपभोक्ताओं को उत्पाद का अंदर लेने के साथ-साथ खेत से लेकर पैक तक की यात्रा के बारे में जानने का अवसर देता है। लेज के इन पैक की खासियत है पुरुष और महिला किसानों के हाथ से बने चित्र, जिनके चारों ओर खेती और फसल कटाई के जीवंत दृश्य दर्शाए गए हैं, जो मिट्टी से स्नेह तक की यात्रा को जीवंत कर देते हैं। लेज का यह सीमित संस्करण वाले पैक उपभोक्ताओं के लिए मिट्टी की चिढ़ी लेकर आए हैं। लेज की एक फिल्म जो किसान और जमीन के बीच के रिश्ते को दर्शाती है।

रुपया नए निचले स्तर पर, डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 88.27 पर बंद हुई भारतीय मुद्रा

नई दिल्ली। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली करने और भारत के आईटी सेक्टर पर अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ लगाए जाने की आशंका की वजह से भारतीय मुद्रा रुपये डॉलर की तुलना में अभी तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। भारतीय मुद्रा रुपये ने आज डॉलर की तुलना में 11 पैसे फिसल कर सबसे कमजोर क्लोजिंग का नया रिकॉर्ड बनाते हुए 88.27 (अनॉतिम) के स्तर पर आज के कारोबार का अंत किया। रुपये ने आज के कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ ही की थी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा ने आज सुबह डॉलर के मुकाबले 16 पैसे की बढ़त के साथ 88.10 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। हालांकि आज का कारोबार शुरू होने के बाद रुपये पर लगातार दबाव बढ़ता गया, जिसकी वजह से रुपये की गिरावट बढ़ती चली गई। विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से अपने पैसे की निकासी करने और अमेरिका द्वारा भारत के आईटी सेक्टर पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की अफवाह की वजह से मुद्रा बाजार में रुपये पर काफी दबाव बढ़ गया। इस अफवाह की वजह से रुपया डॉलर की तुलना में अभी तक सबसे निचले स्तर 88.38 तक गिर गया। हालांकि बाजार में अतिरिक्त टैरिफ से जुड़ी खबरों का खंडन आने के बाद रुपये की स्थिति में कुछ सुधार हुआ।

चार्टर्ड स्पीड ने 855 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए दाखिल किया डीआरएचपी

नई दिल्ली। अहमदाबाद की चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड कंपनी ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) के लिए पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया है। कंपनी की योजना इस इश्यू के जरिए 855 करोड़ रुपये जुटाने की है। शेयरों को एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। पूंजी बाजार नियामक सेबी के समक्ष जमा दस्तावेज के मुताबिक पांच रुपये अंकित मूल्य वाले प्रस्तावित ये इश्यू 655 करोड़ रुपये तक के नए शेयरों का निगम और प्रमोटरों पंकज गांधी और अलका पंकज गांधी का क्रमशः 200 करोड़ रुपये तक के बिक्री प्रस्ताव है। इसमें पात्र कारोबारियों का दस्तखता आरक्षण भी शामिल है, जबकि कर्मचारी आरक्षण वाले हिस्से में बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को छूट भी दी जा रही है। कंपनी 655 करोड़ रुपये के नए निगम से प्राप्त राशि का उपयोग 98 करोड़ रुपये मूल्य की इलेक्ट्रिक बसें में निवेश करेगी। इसके अलावा कंपनी 396.4 करोड़ रुपये का कुछ उधारों का पूर्व-भुगतान या पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी।

रेनॉल्ट भी कार की कीमतों में करेगी 96,395 रुपये की कटौती, नई दरें 22 सितंबर से होंगी लागू

एजेंसी
नई दिल्ली। टाटा मोटर्स के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा और रेनॉल्ट इंडिया ने शनिवार को अपनी कारों की कीमतों में 96,395 रुपये तक की कटौती का ऐलान किया है। नई कीमतें नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से शुरू होने वाली सभी कारों की डिलीवरी पर लागू होंगी। हालांकि, देशभर के डीलरशिप पर संशोधित कीमतों पर बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। रेनॉल्ट इंडिया ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि वह अपनी कारों की कीमतों में 96,395 रुपये तक की कटौती करेगी, जिससे हाल ही में जीएसटी की दरों में की गई कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को मिलेगा। कंपनी ने कहा कि नई कीमतें नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर, 2025 से शुरू होने वाली सभी डिलीवरी पर लागू होंगी। रेनॉल्ट इंडिया के एमडी वेंकटराम मामिलपल्ले ने जारी बयान में कहा, जीएसटी 2.0

दिनभर उतार-चढ़ाव के बाद सपाट स्तर पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 715 अंक लुढ़का

एजेंसी
नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव का सामना करने के बाद सपाट स्तर पर मिले-जुले परिवर्तन के साथ बंद हुआ। आज के कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी। बाजार खुलते ही खरीदारी के सपोर्ट से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में मामूली तेजी भी आई। इसके बाद बिकवाली का दबाव बन जाने की वजह से दोनों सूचकांक अपनी सारी बढ़त गंवा कर लाल निशान में गिर गए। हालांकि दिन के

दूसरे सत्र में एक बार फिर खरीदारों ने मोर्चा संभाला, जिसकी वजह से शेयर बाजार निचले स्तर से रिकवरी करने में सफल रहा। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.009 प्रतिशत की कमजोरी के साथ और निफ्टी 0.027 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे। आज दिनभर के कारोबार के दौरान ऑटोमोबाइल और मेटल सेक्टर की शेयरों में जमकर खरीदारी होती रही। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, हेल्थ केयर, कंज्यूम ड्यूरैबल और बैंकिंग इंडेक्स भी

मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में आया 32,500 करोड़ का निवेश, 17,000 लोगों को मिलेगा रोजगार

एजेंसी
भोपाल। मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र आया 32,500 करोड़ का निवेश आया है। यह प्रदेश सरकार की निवेश परक सार्थक प्रयासों और विकासउन्मुख नीतियों सकारात्मक परिणाम बताया जा रहा है। टॉरेंट पॉवर और अडानी पॉवर जैसी बड़ी कंपनियों ने तो अब ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रदेश में काम करना भी शुरू कर दिया है। टॉरेंट पॉवर कंपनी 22 हजार करोड़ और अडानी पॉवर कंपनी 10 हजार 500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 17,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जनसंपर्क अधिकारी क्रांतिदीप अलुने ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निवेश संवर्धन प्रयासों के फलस्वरूप ऊर्जा क्षेत्र और

ज्यादा मजबूत हो रहा है। ऊर्जा सुरक्षा बढ़ रही है। मध्य प्रदेश पॉवर सरप्लस राज्य के रूप में पहचान बना चुका



है। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों से अब इस क्षेत्र में नया निवेश आ रहा है। उन्होंने बताया कि टॉरेंट पॉवर 1600 मेगावॉट थर्मल प्रोजेक्ट के

कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) से 1,600 मेगावॉट के कोयला आधारित बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) दे दिया है। यह

जापान के इवाते प्रीफेक्चर के वाइस गवर्नर और जेआईसीए के प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात के मुख्यमंत्री से की भेंट

एजेंसी
अहमदाबाद। जापान के इवाते प्रीफेक्चर के वाइस गवर्नर सासाकी जून के नेतृत्व में जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के प्रतिनिधिमंडल ने गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भेंट की। राज्य सूचना विभाग ने अपने बयान में बताया कि यह प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2025 में सहभागी होने के लिए भारत आया है। इस बीच प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात में कार्यरत जापानी सेमीकॉन इंस्ट्रूज की यात्रा की। यह प्रतिनिधिमंडल धोलेरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसआईआईए) में कार्यरत सेमीकॉन उद्योगों की साइट भ्रमण करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मिला। उसने राज्य सरकार द्वारा जापानी उद्योगों को मिल रहे सहयोग पर आभार व्यक्त किया। राज्य में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के तेजी से बढ़ रहे दायरे से भी यह प्रतिनिधिमंडल प्रभावित हुआ

है।मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस बैठक-चर्चों के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत-जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों से राज्य में



सेमीकंडक्टर सेक्टर में जापानी उद्योगों के अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। गुजरात चार सेमीकंडक्टर प्लांट वाला राज्य है और सेमीकंडक्टर हब बनने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है।इस संदर्भ में उन्होंने राज्य में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए जापान के इवाते प्रीफेक्चर

क्षेत्रों में दीर्घकालीन परस्पर सहयोग की उत्सुकता व्यक्त की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एम. के. दास, वित्त विभाग के प्रधान सचिव टी. नटराजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव एं. भारती तथा वरिष्ठ अधिकारी सहभागी हुए।

तूतुकोडी का वीओसी बंदरगाह बना देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाला बंदरगाह

एजेंसी
तूतुकोडी (तमिलनाडु)। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने आज यहां वी.ओ. चिंदरनार बंदरगाह पर देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना शुरू की, जिससे यह बंदरगाह ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला बंदरगाह बन गया।इस मौके पर सोनोवाल ने 35.34 करोड़ रुपये की हरित मेथनॉल बंकरिंग सुविधा, 59.20 करोड़ रुपये का 6 मेगावाट प्रेम फार्म, 90 करोड़ रुपये का मल्टी-कार्गो बर्थ, 34.77 करोड़ रुपये की 4-लेन सड़क और 3 करोड़ रुपये का तमिलनाडु समुद्री विरासत संग्रहालय की नींव भी रखी। साथ ही, 1.46 करोड़ रुपये का 400 किलोवाट रफ्टपीट सौर संयंत्र और 24.50 करोड़ रुपये का कोल

जेटी-कन्वेयर सिस्टम भी शुरू किया। उन्होंने रेल कनेक्टिविटी के लिए आईपीआरसीएल और हरित



मोबिलिटी के लिए एनटीपीसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। इसके तहत 3.87 करोड़ रुपये की हरित हाइड्रोजन परियोजना बंदरगाह की स्ट्रीट लाइटों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हाइड्रोजन

तृतीकोरिन हरित शिपिंग कॉरिडोर ने सहयोगी साबित होगी। इस सौर संयंत्र से बंदरगाह की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 1.04 मेगावाट हो गई, जो देश के बंदरगाहों में सबसे ज्यादा है। ये परियोजनाएं तमिलनाडु में हजारों

नौकरियां पैदा करेंगी, व्यापार बढ़ाएंगी और 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगी। सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का समुद्री क्षेत्र अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। साल 2047 तक विकसित भारत की उनकी अपील /आह्वान गति, पैमाने, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का मिश्रण है। तमिलनाडु में शुरू की जा रही परियोजनाएं हजारों रोजगार सृजित करेंगी, व्यापार को बढ़ावा देंगी और वैश्विक निवेश आकर्षित करेंगी। इससे तमिलनाडु 2027 तक भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। वीओसी बंदरगाह नवीकरणीय ऊर्जा और हरित बंकरिंग के साथ भारत का हरित हाइड्रोजन और अमोनिया केंद्र बनेगा।

टाटा मोटर्स के यात्री वाहन 22 सितंबर से 1.45 लाख रुपये तक होंगे सस्ते

एजेंसी
नई दिल्ली। वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर में हुई कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देने के इरादे से अपने यात्री वाहनों की कीमतों में 65 हजार रुपये से 1.45 लाख रुपये तक की कटौती करने का ऐलान किया है। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगी। टाटा मोटर्स ने जारी बयान में कहा कि कंपनी ने अपने यात्री वाहनों के लिए कर की दरों में कटौती करने का फैसला जीएसटी परिषद के बुधवार को लिए गए फैसले के अनुरूप लिया है। कंपनी ने कहा कि यात्री वाहनों की कीमतों में यह कटौती नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएगी।। मुंबई स्थित कंपनी ने कहा कि टाटा मोटर्स की छोटी टाटा डिगोए अनव 75,000 रुपये सस्ती हो जाएगी, जबकि टिगोर के दाम में 80 हजार रुपये और अल्ट्रोज की कीमत में 1.10 लाख रुपये की कटौती होने जा रही है। इसी तरह कॉम्पैक्ट एसयूवी चंच' की कीमत 85,000 रुपये और नेक्सॉन के दाम 1.55 लाख रुपये तक घट जाएंगी। कंपनी ने

बताया कि मिड-साइज मॉडल 'क्वर्क' की कीमत में 65,000 रुपये की कमी होगी। वहीं, प्रीमियम एसयूवी 'मॉडल चैरियर' और 'चरफरारी' की कीमतों में क्रमशः 1.4 लाख रुपये और 1.45 लाख रुपये तक की कटौती की जाएगी। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के प्रबंध निदेशक (एमडी) शैलेश चंद्रा ने कहा, प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण, वित्त मंत्री की मंशा और हमारी 'चाहक प्रथम' नीति के अनुरूप टाटा मोटर्स इस कर सुधार का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।'' चंद्रा ने कहा कि जीएसटी कटौती से टाटा मोटर्स की लोकप्रिय करें और एसयूवी ज्यादा ग्राहकों की पहुंच में आएंगी, जिससे पहली बार वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को मदद मिलेगी और नए युग के परिवहन की तरफ बदलाव को गति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि जीएसटी की नई कर के तहत अब 1,200 सीसी तक के पेट्रोल, एलपीजी एवं सीएनजी वाहन और 1500 सीसी तक के डीजल वाहन (लंबाई 4,000 मिमी से कम) 18 फीसदी की दर में आएंगे।

मुनाफा हो गया। आज दिनभर के कारोबार में बीएसई में 4,260 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 2,134 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 1,957 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 169 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,776 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1,411 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में और 1,365 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 14 शेयर बढ़त के साथ और 16 शेयर गिरावट

के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 27 शेयर हरे निशान में और 23 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 294.41 अंक उछल कर 81,012.42 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होने ही ये सूचकांक खरीदारी के सपोर्ट से 318.55 अंक की बढ़त के साथ 81,036.56 अंक तक पहुंच गया। इस उछाल के तुरंत बाद बिकवाली का दबाव बन गया, जिसकी वजह से इस सूचकांक की चाल में गिरावट आ गई। लगातार हो रही बिकवाली के

प्रधानमंत्री के स्वदेशी अभियान को नागपुर सम्मेलन में मिलेगी धार: प्रवीण खंडेलवाल

एजेंसी
नई दिल्ली। सांसद एवं कम्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना अब तेजी से साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से थोपा गया टैरिफ एक चुनौती नहीं, बल्कि अवसर है। खंडेलवाल ने यहां कांस्टीट्यूशन क्लब में कैट, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमटी एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता मोर्चा द्वारा आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग यह प्रण लेता है कि हर दुकान, हर बाजार, हर रेहड़ी पर स्वदेशी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विदेशी वस्तुओं का विकल्प केवल स्वदेशी ही होगा। अमेरिकी टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार-प्रसार एवं उपभोग को जन-आंदोलन बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त रूप से घोषणा की गई कि 15 और 16 सितंबर को नागपुर में 'व्यापारी जुटान -राष्ट्रीय सम्मेलन' आयोजित होगा, जिसमें देशभर से 400 से अधिक व्यापारी नेताओं, हॉकर्स संगठनों, उपभोक्ता मंचों एवं उद्योग प्रतिनिधियों को मौजूदगी होगी। इस सम्मेलन के बाद राष्ट्रीय स्वदेशी अभियान पूरे देश के गांव-गांव, कस्बों और शहरों तक चलाया जाएगा। व्यापारी जुटान को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि देशभर में 10 करोड़ से अधिक व्यापारी, रेहड़ी-पट्टरी वाले और छोटे रिटेल व्यवसायी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 82 लाख करोड़ रुपये के व्यापार से जुड़े हैं। आने वाले 10 वर्षों में यह आंकड़ा 190 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन अमेजन और वालमार्ट जैसी बहुपक्षीय ई-कॉमर्स कंपनियां अचैत माध्यम से बाजार में घुसपैट कर रही हैं, जिससे छोटे व्यापारी गंभीर संकट में हैं।

भारतीय कपड़ा उद्योग पर कितनी है संकट की घड़ी अमेरिकी टैरिफ का विकल्प हैं 40 नए बाजार

एजेंसी
नई दिल्ली। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय कपड़ा और परिधान उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक का भारी-भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला केवल एक व्यापारिक कदम नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार समीकरणों में बदलते संतुलन का भी प्रतीक है। इस निर्णय ने भारतीय कपड़ा उद्योग को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अमेरिका भारत के लिए वर्षों से एक प्रमुख निर्यात बाजार रहा है। लेकिन हर संकट अपने भीतर अवसर भी छिपाए होता है। सवाल यह है कि क्या भारत इस चुनौती को अवसर में बदल पाएगा? क्या हमारे कपड़ा निर्यातक अमेरिकी बाजार पर निर्भरता घटाकर नए बाजारों में टिकाऊ पैठ बना सकेंगे? और क्या केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस विशाल उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में और मजबूत बना पाएंगी?भारतीय कपड़ा उद्योग का

अतीत इस संबंध में बताता है कि यह क्षेत्र कठिनाइयों से घ घसराकर पीछे हटने वाला नहीं है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चमरा गई थी और लाखों श्रमिकों की रोजी-रोटी पर संकट मंडरा रहा था, तब भी यही उद्योग धीरे-धीरे उठ खड़ा हुआ और आज पहले से अधिक मजबूत दिखाई देता है। यही वजह है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का दावा है कि अमेरिकी टैरिफ से झटका जरूर लगेगा, लेकिन यह पूरे उद्योग को डिगा नहीं पाएगा। भारत का कुल कपड़ा और परिधान निर्यात लगभग 40 से 45 बिलियन डॉलर का है। इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी केवल 8 से 10 प्रतिशत है। इस हिस्से में भी 50 से 60 प्रतिशत निर्यात सिर्फ 5 से 7 देश व्यापारी करते हैं। यानी अमेरिका पर निर्भरता इतनी व्यापक नहीं है जितनी दिखाई देती है। दरअसल, इसका अर्थ यह हुआ कि बड़े निर्यातक तो प्रभावित होंगे, लेकिन

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ दो दिवसीय ‘पीएसबी मंथन’ करेगा वित्त मंत्रालय

एजेंसी
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के शीर्ष नेतृत्व के साथ अगली पीढ़ी के बैंकिंग सुधारों पर दो दिवसीय 'पीएसबी मंथन' करेगा। 12 सितंबर से शुरू होने वाले 'पीएसबी मंथन' में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के लोग भाग लेंगे। इसका मकसद देश में बैंकिंग गतिविधियों को आसान बनाना है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पीएसबी के शीर्ष नेतृत्व के साथ अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए बैंकों के साथ इस तरह का पिछला मंथन अप्रैल, 2022 में आयोजित किया गया था। तब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संपूर्ण नेतृत्व ने वित्तीय सेवा विभाग (डीओएफ) की देखरेख में उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईज) सुधारों को अगले स्तर तक ले जाने पर चर्चा की थी। 'ईज' नवंबर 2017 में आयोजित

च्यीएसबी मंथन' की सिफारिशों पर आधारित है। पिछले मंथन में पीएसबी के कामकाज की समीक्षा करने और ग्राहक सेवा, डिजिटलीकरण, मानव संसाधन प्रोत्साहन, कॉरपोरेट प्रशासन



और सहयोग में सुधार के उपाय सुझाने के लिए छह कार्य समूहों का गठन किया गया था। पीएसबी मंथन का नया दौर पीएसयू बैंकों के संचयी लाभ के 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2024-25 में 1.78 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की पृष्ठभूमि में आयोजित होगा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 26 फीसदी की वृद्धि है।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.51 अरब डॉलर बढ़कर 694.23 अरब डॉलर पर

नई दिल्ली। देश का विदेश मुद्रा भंडार 29 अगस्त को समाप्त हफ्ते में 3.51 अरब डॉलर बढ़कर 694.23 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इससे पिछले हफ्ते में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 4.39 अरब डॉलर घटकर 690.72 अरब डॉलर रह गया था। रिजर्व बैंक



ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने जारी आंकड़ों में बताया कि 29 अगस्त को समाप्त हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक, विदेशी मुद्रा आरक्षित 1.69 अरब डॉलर बढ़कर 583.94 अरब डॉलर हो गई। इस दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.77 अरब डॉलर बढ़कर 86.77 अरब डॉलर पर पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक कि इस दौरान विशेष आरक्षण अधिकार (एसडीआर) चार करोड़ डॉलर बढ़कर 18.77 अरब डॉलर हो गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास भारत का आरक्षित भंडार भी 1.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.75 अरब डॉलर पर पहुंच गया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इससे पहले सितंबर, 2024 के अंत में बढ़कर 704.88 अरब डॉलर के अवकाश के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।

विदेश/विज्ञापन

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में डकैतों ने वाहनों पर की गोलीबारी, 10 लोगों को किया अगवा

एजेंसी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हथियारबंद डकैतों ने वाहनों पर हमला कर 10 लोगों को अगवा कर लिया। यह वारदात बुधवार देर रात रहीम यार खान जिले के भोंग शरीफ के पास एम-5 मोटर-वे पर हुई। इस दौरान डकैतों ने गुजर रहे वाहनों को निशाना बनाया। गोलीबारी में कई लोग घायल भी हो गए। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर में पुलिस के हवाले से बताया गया कि घातक हथियारों से लैस डकैतों के एक समूह ने कारों, दो बसों, ट्रकों और ट्रैलरों पर गोलीबारी की। गोलीबारी में एक महिला और एक बच्चे सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें रहीम यार खान के शोध जायद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोटर-वे पर यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया। पुलिस ने पुष्टि की कि डकैत 10 लोगों को अगवा कर अपने साथ ले गए हैं। इनमें यात्री और ट्रक ड्राइवर शामिल हैं। पुलिस सुर्जों ने पुष्टि की है कि गोलीबारी के बाद हमलावर नदी किनारे के कच्चा इलाकों की ओर भाग गए। कई ट्रक मोटरवे पर ही छोड़ दिए गए, और उनके कारक दल के सदस्य लपता हो गए। इससे कुछ दिन पहले रहीम यार खान पुलिस ने कुख्यात ईंधर गिरोह के ठिकाने पर ड्रोन हमले किए थे।

नमाज के बाद मचा हंगामा : सूफी संत की कब्र तोड़ी

ढाका। बांग्लादेश में दो बड़ी हिंसक वारदातें सामने आईं। उग्र कट्टरपंथियों ने सूफी संत नूरा पागला की मजार से शव निकालकर आग के हवाले कर दिया। वहीं, राजधानी ढाका में जातीय- बांग्लादेश दो भयावह घटनाओं से दहल उठा। पहली वारदात में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने एक सूफी संत की मजार को अपवित्र कर उनके शव को आग के हवाले कर दिया। दूसरी और, जातीय पार्टी के दपस्तर में भीषण आगजनी की गई। इन घटनाओं ने पूरे देश में दहशत और तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। गीतलेख है कि पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में लगातार हिंसा बढ़ रही है, जहां खासकर मुस्लिम कट्टरपंथी अल्पसंख्यक समुदायों को अपना निशाना बना रहे हैं। पश्चिमी राजबारी जिले में जुमे की नमाज के बाद हालात अचानक बिगड़ गए। कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सूफी दरवेश नूरा पागला की कब्र पर हमला कर दिया। नूरा पागला का निधन करीब दो हफ्ते पहले हुआ था। हमलावरों ने उनकी कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला और आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी दरगाह को भी तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया। इस घटना के बाद नूरा पागला के समर्थकों और हमलावरों के बीच हिंसक झड़प छिड़ गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए।

रूस ने व्हाट्सएप को निशाना बनाया, इंटरनेट ब्लैकआउट बढ़ने पर नया च्युपर-ऐप’ किया लांच

पॉस्को। रूस के मीडिया नियामक रोस्कोम्नाडजोर द्वारा अगस्त के मध्य में लगाए गए नए प्रतिबंधों का लाखों रूसी नागरिकों को सामना करना पड़ रहा है। ये प्रतिबंध रूस में सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग एप व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए की जाने वाली काल पर लगाए गए हैं। ज़ोबीसी के मुताबिक इसी समय रूसी फर्म ने मैक्स नाम से एक नए राष्ट्रीय मैसेंजर को लांच किया है, जिसे क्रेमलिन नियंत्रित करता है। यदि देश में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के मासिक उपयोगकर्ताओं की आंकड़ों की बात करें तो कुल 14.30 करोड़ की आबादी में से व्हाट्सएप और टेलीग्राम के मासिक उपयोगकर्ताओं की संख्या क्रमशः 9.7 और नौ करोड़ होने का अनुमान है। व्हाट्सएप की मालिकाना कंपनी मेटा को रूस में एक चरमपंथी संगठन घोषित किया गया है। यह एप विशेष रूप से बुजुर्ग लोगों के बीच खासा लोकप्रिय है क्योंकि इसमें पंजीकरण करना और इसका उपयोग करना बहुत आसान है। रूस के कुछ हिस्सों में खासकर दूरदराज और कम कनेक्टिविटी वाले इलाकों में व्हाट्सएप दोस्तों और सहकर्मियों के साथ चैटिंग से कहीं बढ़कर है। मोबाइल ब्राउजिंग जब कभी-कभी बहुत धीमी हो जाती है, तो लोग स्थानीय मामलों में एक-दूसरे से बात करने, टैक्सी बुक करनेऔर खबरें साझा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।

अमेरिका और भारत के बीच तनाव: ट्रम्प के मंत्री ने दी भारत को चेतावनी, रखी तीन शर्तें

वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन के एक वरिष्ठ मंत्री ने भारत को एक कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे च्चक या दो महीने’ के भीतर कुछ मुद्दों पर माफी मांगनी होगी। मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। यह चेतावनी हाल ही में हुए एक अज्ञात व्यापारिक या कूटनीतिक विवाद से जुड़ी हुई मानी जा रही है। मंत्री ने भारत से माफी मांगने के लिए तीन शर्तें भी रखी हैं। पहली शर्त यह है कि भारत को एक विशेष व्यापारिक समझौते में अमेरिका को प्राथमिकता देनी होगी। दूसरी शर्त में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा मामले में भारत से सहयोग की मांग की गई है। तीसरी और सबसे कठोर शर्त यह है कि भारत को एक हालिया घटना के लिए सार्वजनिक तौर पर खेद व्यक्त करना होगा। इस बयान के बाद भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, कूटनीतिक हलकों में इस बयान को बेहद आपत्तिजनक और कूटनीतिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जा रहा है।

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के आग्रह को ठुकराया, कहा- नहीं रुकेगा अफगान शरणार्थियों का निर्वासन

एजेंसी काबुल। पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों के मौजूदा निर्वासन को निलंबित करने के संयुक्त राष्ट्र के आह्वान को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कठोर रुख अपनाते हुए कहा है कि संघीय सरकार के फैसले में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने पत्रकारों को बताया कि निर्वासन नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इस प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया जाएगा। इससे पहले, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त फ्रिलिपो ग्रांडी ने अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में आए विनाशकारी भूकंप का हवाला देते हुए इस्लामाबाद से निर्वासन रोकने का



आग्रह किया था। अफगानिस्तान में मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत रिचर्ड बनेट ने भी

पाकिस्तान से निष्कासन में देरी करने की अपील की। इसके जवाब में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने जोर



देकर कहा कि निर्वासन तो जारी रहेगा, लेकिन देश कानूनी रूप से प्रवेश करने के इच्छुक अफगानों के

लिए उदार वीजा नीति बनाए रखेगा। पाकिस्तान ने बिना दस्तावेज वाले अफगान शरणार्थियों और जिनके अस्थायी निवास परमिट की अवधि समाप्त हो गई है, उनके लिए रव्चेख से देश छोड़ने की समय सीमा 1 सितंबर तक की थी। मानवाधिकार समूहों और शरणार्थी अधिकवक्ताओं ने पाकिस्तान की सामूहिक निष्कासन योजना की बार-बार आलोचना की है। पर्यवेक्षकों ने चेतावनी दी है कि संयुक्त राष्ट्र की अपीलों की अनदेखी करने से पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में और तनाव पैदा हो सकता है। साथ ही संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पहले से ही विस्थापित अफगान शरणार्थियों के लिए मानवीय संकट और भी बदतर हो सकता है।

नागरिकों की व्यापक हत्याओं के दावों को भी खारिज कर दिया है। ‘अनरेवेलिंग द ट्रुथ: ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ अनमार्कंड एंड अनआइडेंटिफाइड ग्रेक्स इन कश्मीर वैली’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि 2,493 कब्रें विदेशी हैं। हालांकि, सबसे चौकाने वाला खुलासा यह है कि सिर्फ 0.2 प्रतिशत कब्रें (9) नागरिकों की हैं। यह रिपोर्ट दो प्रमुख मुद्दों को सुलझाती है। पहला, कश्मीर में स्थानीय लोगों की तुलना में पाकिस्तानी आतंकी ज्यादा सक्रिय थे। दूसरा, कई लोगों ने

आतंकवादियों को सुलझाती है। पहला, कश्मीर में स्थानीय लोगों की तुलना में पाकिस्तानी आतंकी ज्यादा सक्रिय थे। दूसरा, कई लोगों ने

आतंकवादियों को सुलझाती है। पहला, कश्मीर में स्थानीय लोगों की तुलना में पाकिस्तानी आतंकी ज्यादा सक्रिय थे। दूसरा, कई लोगों ने



जमील अहमद के रूप में हुई है। हमलें के समय दोनों सदे कपड़ों में थे। द बलोचिस्तान पोस्ट के

अनुसार, इस हमले की फिलहाल किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है।



अपने कमांड सेंटर के तौर पर कर रहा था। इस हमले के बाद पूरे इलाके में तबाही का मंजर देखा गया है। हमस के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजराइल के इस हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। मरने वालों में लश्करा के अल्ला आम नागरिक भी शामिल हैं। इजराइल ने कहा है कि वह उन ठिकानों को निशाना बना रहा है, जहाँ से हमस उसके नागरिकों पर रॉकेट हमले करता है। इजराइल और हमस के बीच हुई इस झड़प के बाद सामने लाने के लिए किया जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि जिन कब्रों के बारे में पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, उनसे जुड़ी यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने इस्लामाबाद को बेनकाब करने में मददगार साबित होगी।

ट्रंप के रूख में बड़ा बदलाव, बोले भारत के साथ रिश्ते अहम, मोदी अच्छे दोस्त

एजेंसी वाशिंगटन। अमेरिका द्वारा भारत पर भारी टेरिफ लगाये जाने के बाद दोनों देशों में चल रही तनाती के बीच पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ संबंधों को विशेष और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अच्छ दोस्त बताये जाने वाले बयान और उस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सकारात्मक जवाब के बाद इस मुद्दे के समाधान की उम्मीद बढ़ गयी है। श्री ट्रंप ने अपने पहले दिये गये बयान से बारह घंटे में ही पलटते हुए व्हाइट हाउस में भारत के साथ रिश्तों को बेहद खास बताते हुए कहा था कि वह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वह महान प्रधानमंत्री हैं। दोनों देशों के

संबंधों के बारे में श्री ट्रंप ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी के



साथ अच्छी बनती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साथ ही यह भी कहा कि लेकिन उन्हें भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर नाराजगी भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों के

बीच कभी-कभी इस तरह की बातें हो जाती हैं।

श्री मोदी ने शनिवार को इसके



जवाब पर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि वह श्री ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा , राष्ट्रपति

ट्रम्प की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। उल्लेखनीय है कि श्री ट्रंप ने इससे पहले चीन में प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनिपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद कहा था कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हथौं खो दिया है। लेकिन बारह घंटे के अंदर ही श्री ट्रंप ने अपने रूख को बदलते हुए भारत के साथ रिश्तों को अहम बताया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भी प्रशंसा की और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है।

जॉर्जिया में हुंडई के संयंत्र से दक्षिण कोरियाई बैटरी निर्माता के 475 कर्मचारी गिरफ्तार

एजेंसी वाशिंगटन (अमेरिका)। आब्रजन अधिकारियों ने दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य जॉर्जिया स्थित हुंडई के एक संयंत्र से 475 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह सभी एक प्रमुख दक्षिण कोरियाई बैटरी निर्माता के कर्मचारी है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे एक ही स्थान पर सबसे बड़ा होमलैंड सुरक्षा प्रवर्तन अभियान बताया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, जॉर्जिया में होमलैंड सुरक्षा जांच के प्रभारी विशेष एजेंट स्टॉवन श्रैक ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि एजेंटों ने गुरुवार को जॉर्जिया के एलाबेल में सवाना के पास हुंडई के इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी संयंत्र के निर्माण स्थल से 475 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से अधिकांश दक्षिण कोरियाई नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई कई महीनों तक चली एक जांच का परिणाम है। विशेष एजेंट श्रैक ने कहा कि



डोनाल्ड ट्रंप ने टिप्पणी की, मैं कहीं का कि वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर वेनेजुएला ने फिर से अमेरिकी नौसेना के जहाजों के ऊपर से जेट उड़ाए तो बहुत बुरा हो सकता है। ट्रंप ने रक्षा सचिव पीट हेमसेथ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टॉफ के

हमला किया। इस हमले में 11 लोग मारे गए। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि नाव का संचालन ट्रेन डी अरराआ गिराव कर रहा था। अमेरिकी योजनाओं से परिचित एक सूत्र ने पुष्टि की कि अमेरिका ड्रा काटेंटों को निशाना बनाने के लिए कैरिबियन में 10 एफ-35 लड़ाकू विमान भेज रहा है।

अमेरिका अगले साल जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ट्रंप के गोल्फ कोर्स में करेगा

एजेंसी वाशिंगटन (अमेरिका)। अमेरिका अगले साल 2026 में विश्व नेताओं के समूह-20 (जी-20) के शिखर सम्मेलन की मेजबानी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप के फ्लोरिडा के डोरल स्थित गोल्फ कोर्स और स्पा में करेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मियामी में जी-20 सम्मेलन आयोजित करने के अपने निर्णय की घोषणा की। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने शिखर सम्मेलन की तैयारियों का निम्ना राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट को सौंपा है। राष्ट्रपति ने कहा कि वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट इस सम्मेलन का एजेंडा तैयार करने की योजना बनाई थी। व्यापक आलोचना के बाद उन्होंने यह विचार त्याग दिया। अंततः, कोविड-19 महामारी की शुरुआत के कारण इस

सम्मेलन को रद्द कर दिया गया और वचुअल रूप से आयोजित किया गया। यह रिसॉर्ट ट्रंप ने 2012 में 150 मिलियन डॉलर में खरीदा था।



ट्रंप ने 150 मिलियन डॉलर में खरीदा था ट्रंप ने 2020 में इस रिसॉर्ट में जी-7 शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई थी। व्यापक आलोचना के बाद उन्होंने यह विचार त्याग दिया। अंततः, कोविड-19 महामारी की शुरुआत के कारण इस

चार गोल्फ कोर्स हैं यह पहली बार 1960 के दशक में खुला था। मेट्रो मियामी के घनी आबादी वाले इलाके में स्थित यह मियामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उड़ान मार्ग के नीचे स्थित है। इसमें चार गोल्फ कोर्स, 48,000 वर्ग फीट का एका, 125 फीट की स्लाइड

बलोचिस्तान में ईरान सीमा के पास पाकिस्तान के दो सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या

एजेंसी कटा (बलोचिस्तान) । पाकिस्तान के प्रांत बलोचिस्तान में ईरान की सीमा के पास केच जिले के मांड इलाके में हुए एक सशस्त्र हमले में दो सुरक्षाकर्मी मारे गए। अधिकारियों के अनुसार, यह हमला कोह-पुशात बाजार में हुआ। सशस्त्र हमलावरों ने मोटरसाइकिल सवार सुरक्षाकर्मियों पर घात लगाकर गोलीबारी की।

गोलीबारी में दोनों की मौके पर मौत हो गई।डान अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, लेवी बलों और अन्य सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई कर इलाके को घेर लिया और शवों को पास के एक चिकित्सा केंद्र में पहुंचाया। मारे गए सुरक्षा कर्मचारियों की पहचान अब्दुल अजीज और



जमील अहमद के रूप में हुई है। हमलें के समय दोनों सदे कपड़ों में थे। द बलोचिस्तान पोस्ट के

अनुसार, इस हमले की फिलहाल किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

अनुरोध किया था। पाकिस्तान ने झूठ फैलाने के लिए आधिकारिक चैनलों और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों की सामूहिक हत्याएं हो रही हैं। इन लोगों ने यह भी कहा कि नागरिक मारे जा रहे हैं और इसे अज्ञात कब्रों से जोड़ा गया। हालांकि, रिपोर्ट इस मिथक को तोड़ती है।'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान का 'फेक नरैटिव' अपने चरम पर था। प्रथम फील्ड मार्शल ने दावा किया कि भारत ने ही पाकिस्तान से ऑपरेशन रोकने का



शरीफ चौधरी ने तो यह तक कह दिया कि भारत ने अमुत्तर पर मिसाइलें दागी थीं। भारत हमेशा से पाकिस्तान के झंसे को बेनकाब करने में कामयाब रहा है, लेकिन ऐसी रिपोर्टों और एनआईए की हालिया जांच का इस्तेमाल नई दिल्ली के दूश्िकोण को सामने लाने के लिए किया जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि जिन कब्रों के बारे में पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, उनसे जुड़ी यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने इस्लामाबाद को बेनकाब करने में मददगार साबित होगी।